mediaauditornews@gmail.com Epaperdainikmediaauditor.in वर्ष-30 अंक-159 पृष्ठ-8 मूल्य-3 रूपये

रीवा
10 जून 2026 बुधवार

दैनिक मीडियाऑडीटर

रीवा, सतना एवं मनेन्द्रगढ़ से एक साथ प्रकाशित

: ब्रीफ बॉक्स :

मणिपुर गांवों में सुरक्षा बलों की एंट्री पर नई शर्त

विलेज अथॉरिटी को पहले खबर देनी होगी; नगा गांव में हमले के बाद बढ़ा तनाव

इम्फाल,एजेंसी। मणिपुर में 3 साल से जातीय हिंसा चल रही है। राज्य में पूरी तरह शांति नहीं है। सोमवार को कांगपोकपी जिले के पोंग्रिंगलॉन्ग रोंग्मेई नगा गांव में कुकी उग्रवादी संगठन ने गोलीबारी की। इस घटना के बाद लापता चुन्जांग्लुंग पान्मेई नाम के नगा विलेज गार्ड का शव जंगलों से मिला है। उसके सिर पर गोली मारी गई थी।

नगा समूहों का आरोप है कि केंद्र कुकी समूहों का इस्तेमाल शैडो वॉर (छाया युद्ध) के तौर पर कर रहा है। इसके अलावा चिंग मामांग गांव में अज्ञात हथियारबंद लोगों ने गोलीबारी की, जिसमें एक घायल हुआ है। नगा संगठनों ने सुरक्षा बलों पर पक्षपात का आरोप लगाया है। साथ ही निष्पक्ष जांच की मांग की है।

इस बीच, नोने जिले के लोंग्जांग/ठंगाल गांव की विलेज अथॉरिटी ने राज्य पुलिस, असम राइफल्स, सीआरपीएफ को नोटिस दिया है। इसमें कहा है कि सूचना दिए बिना वे गांवों में नहीं आएं।

अमेरिकी सेना का हेलिकॉप्टर होर्मुज के पास क्रैश

ईरानी बोट्स को उड़ाने के लिए तैनात था, ट्रम्प बोले- दोनों पायलट सेफ

तेहरान/ वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी। अमेरिकी सेना का एक अपाचे हेलिकॉप्टर सोमवार को होर्मुज स्ट्रेट के पास क्रैश हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हेलिकॉप्टर में सवार दोनों पायलट मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने न्यूयॉर्क में पत्रकारों से बातचीत के दौरान घटना की पुष्टि की। ट्रम्प ने कहा है कि हेलिकॉप्टर में सवार दोनों पायलट सुरक्षित हैं। किसी को चोट नहीं आई है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि हेलिकॉप्टर तकनीकी खराबी के कारण गिरा या किसी हमले का शिकार हुआ। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले पर कल रिपोर्ट जारी की जाएगी।

अमेरिकी सेना होर्मुज स्ट्रेट में अपाचे हेलिकॉप्टरों, रूक्क-9 रीपर ड्रोन, F/A-18 और F-35 लड़ाकू विमानों की मदद से सुरक्षा अभियान चला रही है।रिपोर्ट के मुतबाकि, अपाचे हेलिकॉप्टरों का इस्तेमाल छोटे हथियारबंद बोट्स और ड्रोन से होने वाले संभावित खतरों को रोकने के लिए किया जाता है।

जयपुर में पटाखा फैक्ट्री में आग, 4 की मौत

● 5 लोग 90% तक झुलसे, अस्पताल में भर्ती ● रिहायशी इलाके में चल रही थी फैक्ट्री

जयपुर,एजेंसी। जयपुर के खोह नागोरियान इलाके में स्थित पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार सुबह 11 बजे भीषण आग लग गई। अग्निकांड में चार लोगों की मौत हो गई और 5 मजदूर झुलस गए। मरने वालों की अभी पहचान नहीं हुई है। झुलसे आजीम खान, नासीर खान, समीर खान, बिलाल, अब्दुल वाहिद को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार अधिकांश लोग 90 प्रतिशत तक झुलसे हुए हैं।

जयपुर कलेक्टर संदेश नायक ने बताया- पटाखा फैक्ट्री खोह नागोरियान में आयशा नगर तलाई क्षेत्र आईटीआई कॉलेज के पास है। कोई ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग लगी है।

लोग बोले- तीन-चार लोगों को बाहर निकाला, एक बच्चा तड़प रहा था: स्थानीय निवासी मोहम्मद जिया उल हक ने बताया कि फैक्ट्री से डेढ़ सौ मीटर की दूरी पर मेरा घर है। घर से आग की लपटें उठती दिख रही थी। पटाखे फटने की आवाज आ रही थी। आस-पड़ोस के लोग पहुंचे तो पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। पानी का टैंकर भी बुलाया। तीन-चार लोगों को बाहर निकाला। एक बच्चा तड़प रहा था। एक व्यक्ति ने झुलसते हुए मौके पर ही दम तोड़ दिया।

कलेक्टर बोले- जांच की जा रही... जयपुर कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि हादसे में 5 जने गंभीर झुलसे हैं, जिन्हें SMS हॉस्पिटल ले जाया गया है। डेथ को लेकर बाद में कंफर्म कर पाऊंगा। कोई ज्वलनशील होने के कारण आग लगी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है।

प्रशासन के लोग आगजनी के करीब 40 मिनट बाद पहुंचे।

कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

» वकील बोले- गार्ड्स एजेंसी के थे, गोली खान सर ने नहीं चलाई दबाव में एफआईआर हुई

पटना,एजेंसी। फायरिंग मामले में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पुलिस से केस डायरी की भी मांग की है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगले आदेश या अगली सुनवाई तक संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई न की जाए। खान सर की तरफ से पेश हुए वकील अरविंद कुमार महुआर ने कोर्ट से कहा कि गोली आत्मरक्षा में चलाई गई। किसी तरह से भय फैलाना मकसद नहीं था।

खान सर के वकील ने बताया कि खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर 20 जून को सुनवाई होगी। सोमवार को खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर खान सर की ओर से पटना के जिला एवं सत्र कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई। खान सर पर हत्या की कोशिश और हथियारों के अवैध इस्तेमाल मामला दर्ज है।

जेल में बंद सियोरिटी गार्ड मामले में कोर्ट ने सबूत मांगे... सोमवार को इसी मामले में जेल में बंद खान सर के दो सिक्योरिटी गार्ड दीपक कुमार और तालेबर सिंह की जमानत पर भी सुनवाई हुई। उनके वकील अरविंद मउआर ने जज अनुराग वर्मा की अदालत में दलीलें पेश कीं।

इधर, खान सर की कोचिंग पर हमला मामले में जेल में बंद ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद की जमानत पर भी आज फैसला आ सकता है।

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पुलिस से मामले में सबूत मांगे। दोनों सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिका पर भी आज फैसला आ सकता है।

मानसून 5 दिन में 13 राज्यों में पहुंचा

एमपी-यूपी में आंधी-बारिश, केरलम-कर्नाटक में रेड अलर्ट; राजस्थान में हीटवेव की चेतावनी

भोपाल/लखनऊ/जयपुर/पटना,एजेंसी। देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक, मानसून 5 दिन में 13 राज्यों तक पहुंच गया। इसने सोमवार को तेलंगाना में एंट्री ली। मानसून पश्चिमी तट पर अब मुंबई से 150 किमी दूर है। अगले 48 घंटे में यह मुंबई में दस्तक दे सकता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में प्री मानसून बारिश हो रही है।

मध्य प्रदेश के भोपाल में सोमवार को बारिश हुई। यूपी के गोरखपुर और जालौन में भी तेज बारिश हुई। राजस्थान के कुछ हिस्सों में 60 से 120किमी. की रफ्तार से हवा चली।

इधर, राजस्थान के पश्चिमी जिलों में हीटवेव का अलर्ट है। सोमवार को श्रीगंगानगर 45.6डिग्रीतापमान रहा। फलोदी में 44.8डिग्री, जैसलमेर और बीकानेर में 44.4डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौमस विभाग के मुताबिक मंगलवार को 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। पूरे केरलम और कर्नाटक के 2 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है।

प्रति व्यति सुरक्षा खर्च 1प्रतिशत बढ़ा तो क्राइम 0.36प्रतिशत घटा

» एसबीआई की 28 राज्यों पर स्टडी, जहां सीसीटीवी ज्यादा, वहां अपराध कम

नई दिल्ली,एजेंसी। देश की अर्थव्यवस्था और अपराध में गहरा रिश्ता है। अपराध में महज 1% की कमी से अल्पकाल में वास्तविक जीडीपी (विकास दर) 0.11% और दीर्घकाल में 0.133% तक बढ़ जाती है। एसबीआई रिसर्च ने देश के 28 राज्यों की स्टडी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है।

जब सरकार प्रति व्यक्ति के हिसाब से अपने सुरक्षा खर्च में 1% की बढ़ोतरी करती है, तो उस राज्य में अपराध दर लगभग 0.36% घट जाती है। मतलब ये है कि सुरक्षा पर जितना ज्यादा खर्च होगा, जुर्म उतना ही कम होगा।

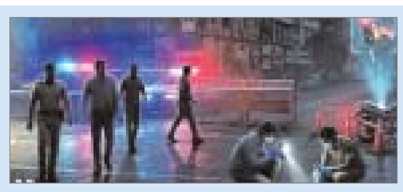

पिछले वर्ष की तुलना में अपराध 6.0% कम... 2024 में देश में कुल 58.86 लाख संज्ञेय (हत्या, दुष्कर्म आदि) अपराध दर्ज हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.0% कम हैं। अखिल भारतीय अपराध दर प्रति लाख आबादी पर वर्ष 2023 के 448.3 से गिरकर 2024 में 418.9 हो गई है। राज्यों में केरल में प्रति लाख आबादी पर सबसे अधिक 1,389 संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए।

बॉम्बे हाईकोर्ट के रिटायर जज का दावा

पूरा परिवार खतरे में: लंदन में बेटी पर हमला हुआ

» दाउदी बोहरा उराधिकार केस में फैसला देने से जुड़ा है मामला

मुंबई,एजेंसी। बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस गौतम पटेल का दावा है कि उन्हें और उनके परिवार को पिछले करीब 10 महीनों से धमकियां मिल रही हैं। पूर्व जज का दावा है कि यह घटनाएं 2024 में दाऊदी बोहरा समुदाय के उत्तराधिकार विवाद पर दिए गए उनके फैसले से जुड़ी हैं।

जज से मांग की जा रही है कि वे एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपना फैसला वापस लें और दावा करें कि उन्हें यह ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया।

बार एंड बेंच और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस पटेल ने अगस्त 2024 में दाऊदी बोहरा समुदाय के उत्तराधिकार विवाद पर फैसला सुनाया था।

उन्होंने सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को दाऊदी बोहरा समुदाय का वैध 53वां दाई-अल-मुतलक घोषित किया था। यह विवाद उनके सौतेले भाई खुजैमा कुतुबुद्दीन और बाद में उनके बेटे ताहिर फखरुद्दीन की ओर से दायर दावों से जुड़ा था। फैसला आने के कुछ समय बाद से ही जस्टिस पटेल और उनके परिवार को धमकी भरे संदेश मिलने शुरू हो गए थे। सितंबर 2025 में एक लेटर भेजकर उनसे फैसले को वापस लेने और सार्वजनिक रूप से उसे गलत बताने की मांग की गई थी।

बेटी पर लंदन में 2 महीने पहले हमला, अब लेटर मिला... जस्टिस पटेल की बेटी अदिति पर 22 अप्रैल 2026 को लंदन में हमला किया गया। वह अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर लौट रही थीं, तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने पीछे से उन पर हमला कर दिया। इस हमले में उनकी नाक की हड्डी टूट गई। यूके पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और पहले मिली धमकियों से जुड़े कनेक्शन की भी पड़ताल कर रही है।

रिटायर जस्टिस के मुताबिक 5 जून को उनकी बेटी अदिति पटेल को फिर से एक गुमनाम पत्र मिला।

रामभद्राचार्य बोले: आशुतोष महाराज का आपराधिक इतिहास जानकर कांप रहा

आशुतोष ने कहा था- जगद्गुरु की हत्या हो सकती है, मेरे पास सबूत

चित्रकूट,एजेंसी। तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज के बयान पर पलटवार किया है। सोमवार को उन्होंने वीडियो जारी कर कहा- आशुतोष ब्रह्मचारी मेरी और मेरे उत्तराधिकारी की छवि खराब करना चाहता है। वह साजिश रच रहा है। मुझे उसका आपराधिक इतिहास जानकर डर लगने लगा है, मैं कांप रहा हूं। इससे पहले, आशुतोष महाराज ने सोमवार को फेसबुक पर वीडियो जारी कर कहा था कि अगर मेरे पूज्य गुरुदेव जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज की हत्या होती है, तो उसकी जिम्मेदारी रामचंद्र दास की होगी, जो उनका उत्तराधिकारी बना बैठा है। वह मेरे गुरु की हत्या कराना चाहता है। मेरे पास इसके पर्याप्त सबूत हैं। आशुतोष महाराज वही हैं, जिन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर 2 बटुकों से यौन शोषण का केस दर्ज कराया था। आशुतोष महाराज पर 21 केस दर्ज हैं।

जगद्गुरु रामभद्राचार्य बोले- आशुतोष से डर लगने लगा है....

जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि आज मन को बहुत आघात लगा है। मैं देश-विदेश में कथा करता हूं। आचार्य धर्म निभाने का प्रयास करता हूं। आशुतोष ब्रह्मचारी के बयानों से मुझे आशंका हुई है कि कहीं कोई साजिश तो नहीं रची जा रही। यह उनकी और उनके उत्तराधिकारी की छवि नष्ट करने का प्रयास हो सकता है। मुझे आशुतोष से डर लगने लगा है।आशुतोष महाराज के शिष्य होने के दावे पर उन्होंने कहा कि मैं अनेक स्थानों पर कथा करने जाता हूं, संभव है कि कहीं आकर आशुतोष ने दीक्षा ले ली हो। मुझे यह पता नहीं था कि उसका मन ऐसा होगा। एक शिष्य द्वारा गुरु की हत्या की आशंका जताना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें, उनके पीठ को और उनके उत्तराधिकारी को खतरा बताया जा रहा है, जो गंभीर विषय है। उन्होंने कहा- इस तरह की घटना की निंदा होनी चाहिए। वह प्रशासन से भी जांच कराने को कहेंगे, जो संवैधानिक रूप से उचित होगा, वही किया जाए।

कश्मीर से लद्दाख जाना हुआ आसान

60 साल का सपना साकार, एशिया की सबसे लंबी जोजिला टनल ब्रेकथ्रू

श्रीनगर,एजेंसी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ ज़ोजिला टनल पहुंचे, ताकि वहां चट्टान की आखिरी दीवार की प्रतीकात्मक खुदाई की जा सके। यह टनल एशियाई महाद्वीप में सबसे लंबी दो-तरफ़ा सड़क टनल है।

वहीं मौके पर मौजूदा लद्दाख सांसद मोहम्मद हनीफा जान ने कहा, 'पिछले 60-70 सालों का सपना अब पूरा होने जा रहा है। मैं लद्दाख की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नितिन गडकरी का धन्यवाद करता हूं। भाजपा सरकार आने के बाद ही इस सुरंग पर व्यावहारिक रूप से काम शुरू हुआ। नितिन गडकरी ने खुद इस परियोजना की निगरानी की। इसका पूरा श्रेय उनके गतिशील नेतृत्व को जाता है। आपको बता दें कि सामरिक दृष्टि से यह सुरंग बेहद अहम है। 1999 के युद्ध के दौरान सरकार और जनता ने यहां सुरंग की जरूरत को महसूस किया था। इस सुरंग से लद्दाख और कारगिल की आर्थिक तरक्की होगी। हर मौसम में खुली रहने वाली यह सड़क बुजुर्गों, छात्रों और मरीजों के लिए फायदेमंद साबित होगी। हमें गडकरी पर पूरा भरोसा है कि यह परियोजना एक साल के भीतर पूरी हो जाएगी। '

प्रोजेक्ट का लगभग 80% काम हो चुका पूरा... वहीं ज़ोजिला प्रोजेक्ट के लिए ICT AIAPL की ओर से अथॉरिटी इंजीनियर यूसुफ़ ने कहा, 'मैं ईरान से हूं। मुझे इस बात पर गर्व है। मुझे खुशी है कि प्रोजेक्ट का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। बाकी 20% को पूरी तरह से पूरा होने में शायद 2 साल और लग सकते हैं। फिर भी, टनल के लिए यह 'ब्रेकथ्रू' (सुरंग के दोनों सिरों का आपस में जुड़ना) एक बड़ी घटना है और हमें खुशी है कि मौजूदा सिस्टम के तहत हम इस प्रोजेक्ट को अच्छे से पूरा कर पाए हैं।

भारत ने पहली बार 12 परमाणु बम तैनात किए:

हमारे एटमी हथियार 2 साल में 180 से बढ़कर 190 हुए; यह पाकिस्तान से 20 ज्यादा

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत ने पहली बार 12 परमाणु हथियार मोर्चे पर तैनात किए हैं। देश का परमाणु हथियारों का भंडार भी 180 से बढ़कर 190 हो गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताजा रिपोर्ट में यह बताया गया है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2025 में भारत ने एक भी परमाणु हथियार तैनात नहीं किया था, लेकिन 2026 में 12 की तैनाती की है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। उसके पास अभी 170 परमाणु हथियार हैं। उसके कितने हथियार तैनात हैं, यह स्पष्ट नहीं है। रूस-अमेरिका की तरह भारत अपने परमाणु हथियारों की सटीक संख्या, क्षमता और नाम आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं करता। SIPRI और दूसरी संस्थाएं केवल अनुमान के आधार पर रिपोर्ट जारी करती हैं।

दुनिया के 9 देशों के पास कुल 12,187 परमाणु हथियार: SIPRI इयरबुक 2026 के अनुसार दुनिया एक नए परमाणु प्रतियोगिता के दौर में पहुंच रही है। अमेरिका, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान समेत सभी परमाणु संपन्न देश अपने हथियारों और डिलीवरी सिस्टम को तेजी से अपग्रेड कर रहे हैं। 2026 की शुरुआत में दुनिया के 9 देशों अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल के पास कुल 12,187 परमाणु हथियार हैं। इसमें से 9,745 परमाणु हथियार सेना के भंडार गृह में हैं, जो इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

भारत की कोशिश- चीन के आखिरी छोर तक पहुंचने वाले हथियार बनाए: भारत लंबी दूरी के ऐसे हथियार बनाने पर फोकस बढ़ा रहा है, ताकि उनकी पहुंच चीन के आखिरी छोर तक हो सके। दरअसल, भारत एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर संतुलित रणनीतिक क्षमता बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। 2020 की हिंसक गलवान झड़प के बाद भारत-चीन सीमा पर भारतीय सैन्य निगरानी भी बढ़ी है। भारत नए परमाणु डिलीवरी सिस्टम पर भी काम कर रहा है। इनमें सबसे अहम है MIRV तकनीक यानी मल्टीपल इंडिपेंडेन्टली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल।

समुद्र में भी बढ़ी परमाणु ताकत... रिपोर्ट में भारत की समुद्री परमाणु क्षमता को भी बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। भारत की परमाणु पनडुब्बियां, खासकर INS अरिहंत, अब देश की 'सेकेंड स्ट्राइक कैपेसिटी' का बड़ा आधार बन रही हैं। SIPRI का अनुमान है कि भारत अब शांति काल में भी सीमित संख्या में परमाणु हथियारों को बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों पर तैनात करने लगा है। इससे दुश्मन के पहले हमले के बाद भी जवाबी कार्रवाई की क्षमता बनी रहती है।

वाह रे वाह! नगर निगम ट्यूबवेल लगाया, पर प्यासे लोगों को पानी नहीं मिल पाया; लोग भटकने को मजबूर

फरीदाबाद, एजेंसी। फरीदाबाद में इस समय पेयजल संकट है। कई सेक्टर व कॉलोनियां ऐसी हैं, जहां तीन से चार दिन में पानी आ रही है। एनआईटी की डबुआ कॉलोनी के कई क्षेत्रों में भी काफी पेयजल संकट बना हुआ है। लोगों ने नगर निगम में शिकायत की है, मगर समाधान नहीं किया गया है। रति राम मार्ग पर स्थित मानस भारती पब्लिक स्कूल के नजदीक लगभग डेढ़ महीना पहले एक ट्यूबवेल लगा दिया गया, जिसे अब तक चालू नहीं किया गया है। पता चला है कि इसमें कुछ कमी रह गई है जिसे पूरा नहीं किया जा रहा है। इस गर्मी में पानी की गंभीर समस्या से स्थानीय निवासी को जूझना पड़ रहा है।

पेयजल आपूर्ति बेहतर करने की मांग: कॉलोनी वासियों की शिकायत है कि पानी उपलब्ध कराने के मामले में नगर निगम गंभीर नहीं है। लोगों को मजबूरी में दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर पानी का इंतजाम करना पड़ रहा है। लोगों ने नगर निगम अधिकारियों के कार्यालय जाकर शिकायत दर्ज कराई है। पेयजल आपूर्ति बेहतर करने की मांग की है।

शहर में पानी की है कमी: फिलहाल शहर में पेजयल किल्लत है। मांग 450 एमएलडी तो आपूर्ति 330 एमएलडी प्रतिदिन हो पा रही है। मांग व आपूर्ति में अधिक अंतर होने की वजह से शहर की काफी आबादी टैंकरों के पानी पर निर्भर है। नगर निगम द्वारा टैंकर मुहैया नहीं कराए जाते। लोगों को अपने स्तर पर इंतजाम करना होता है। सबसे अधिक दिक्कत बल्लभगढ़ व एनआईटी में है। हम पानी के लिए भटकने को मजबूर हो गए हैं। नया ट्यूबवेल लगने के बाद भी घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। जब भी पानी देने की मांग की जाती है तो कोई सुनवाई नहीं करता है। इस गर्मी में जल संकट से परेशान दर्जनों किराएदार शाम को नौकरी से आने के बाद देर रात तक पानी के लिए भटकते नजर आते हैं। कई महीने से पानी नहीं मिलने के कारण दैनिक जीवन प्रभावित हो गया है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी परेशान हैं। कई गलियों के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। लोग मजबूरी में आसपास के क्षेत्र में जाकर पानी भर रहे हैं। - दशरथ गुप्ता ट्यूबवेल को चेक करवा लेते हैं। कोई समस्या होगी तो उसका समाधान कराया जाएगा।

पेयजल आपूर्ति के मामले में लोगों को राहत दी जाएगी

25 लाख से अधिक है शहर की आबादी
25 रेनीवेल हैं यमुना नदी किनारे
1700 ट्यूबवेल हैं
450 एमएलडी की है प्रतिदिन जरूरत
330 एमएलडी हो रही है सप्लाई
40 से अधिक कालोनियों में हैं पेयजल संकट
10 रेनीवेल और लगाए जा रहे हैं नदी किनारे।

गुजरात में साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क का भंडाफोड़, 398 करोड़ रुपये के अवैध लेनदेन में 14 गिरफ्तार

उदयपुर, एजेंसी। गुजरात में पुलिस ने आपरेशन म्यूल हंट 2.0 के तहत साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि 13 म्यूल अकाउंट्स (फर्जी बैंक खातों) के जरिये 398.43 करोड़ रुपये के अवैध लेनदेन से संबंधित 228 अंतरराज्यीय साइबर धोखाधड़ी शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पाटन जिले से 14 लोगों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा आनलाइन धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने और साइबर अपराधियों के वित्तीय नेटवर्क को नष्ट करने के अभियान के तहत की गई। पुलिस ने बताया कि केंद्र सरकार के समन्वय पोर्टल और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीसीआरपी) पर उपलब्ध डाटा के विश्लेषण से पता चला है कि पाटन जिले के हारिज नागरिक सहकारी बैंक में खोले गए कुछ चालू खातों (करेंट अकाउंट) से संदिग्ध लेनदेन हुए हैं। जांचकर्ताओं ने पाया कि साइबर अपराधियों ने कमीशन का लालच देकर बैंक खाते खुलवाते थे। खाताधारकों ने कथित तौर पर एटीएम कार्ड, चेक बुक, सिम कार्ड, मोबाइल नंबर और इंटरनेट बैंकिंग संबंधी क्रेडेंशियल साइबर जालसाजों को दे दिए।

5300 भारतीय सिम कार्ड से कंबोडिया का गिरोह कर रहा था साइबर ठगी, अब ईडी कसेगी शिकंजा

जयपुर, एजेंसी। ईडी ने देश में 5,300 सिम कार्ड की खरीद से जुड़े मामले की जांच शुरू कर दी है। इसका उपयोग कंबोडिया में एक मलेशियाई नागरिक के नेतृत्व वाले गिरोह द्वारा पूरे भारत में साइबर धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए किया गया था। जांच एजेंसी ने पांच जून को लुधियाना के अलावा राजस्थान के किशनगढ़, नागौर और जोधपुर में सात परिसर की तलाशी ली थी। इसी के आधार पर 30 घरेलू बैंक खातों की पहचान हुई। जो इस धोखाधड़ी नेटवर्क का हिस्सा हैं। ईडी ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया गया यह मामला जोधपुर पुलिस की उस प्राथमिकी से जुड़ा है, जिसमें कुछ पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल्स) विक्रेताओं के खिलाफ भारतीय सिम को धोखाधड़ी से सक्रिय करने और उन्हें एक मलेशियाई नागरिक को सौंपने का आरोप लगाया गया था। ईडी के अनुसार कंबोडिया के ठगी गिरोहों से जुड़े कई साइबर अपराध के मामले सामने आए हैं। इनमें डिजिटल अरेस्ट भी शामिल है। इन मामलों में भारतीयों को साइबर अपराध के जरिये फंसाया गया है। ईडी ने बताया कि उसने 2.3 लाख नंबरों (सिम कार्ड) का विश्लेषण किया। इसमें पता चला कि उनमें से लगभग 36 हजार कंबोडिया में सक्रिय थे, जिनमें से लगभग 5,300 का इस्तेमाल वॉट्सएप काल कर पूरे भारत में सैकड़ों करोड़ रुपये के साइबर धोखाधड़ी करने में किया गया। एजेंसी के अनुसार, तलाशी के दौरान सामने आया कि राहुल कुमार झा, मोहम्मद शरीफ और संदीप भट्ट ने प्रकाश भील, रामअवतार राठी, हरीश मालाकार और हेमंत पनवार नामक अन्य सिम विक्रेताओं के साथ मिलकर मलेशियाई नागरिक को सैकड़ों सिम कार्ड की आपूर्ति की। सिम विक्रेताओं के पास एयरटेल, जियो और वोडाफोन इंडिया जैसे दूरसंचार ऑपरेटरों की पीओएस आईडी थी। आरोपित सिम कार्ड पोर्ट करने या नए सिम जारी करने के बहाने कम पढ़े-लिखे और भोले-भाले लोगों को निशाना बनाते थे। हालांकि, उक्त सिम को सक्रिय करते समय उन्होंने अतिरिक्त रूप से अन्य सिम भी सक्रिय कर दिए, जिन्हें बाद में राहुल कुमार झा और उनके सहयोगियों के जरिये कमीशन के बदले में मलेशियाई नागरिक को आपूर्ति की गई।

दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में होगी 41 किमी की वृद्धि, मजेंटा-गोल्डन लाइन के खुलेंगे नए कॉरिडोर, बेहतर होगी कनेक्टिविटी

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली और एनसीआर के अन्य शहरों में आवागमन को सुगम बनाने के लिए मेट्रो विस्तार का कार्य तेजी से चल रहा है। इस वर्ष के अंत तक मेट्रो के तीन और कॉरिडोर शुरू होने की उम्मीद है। इसमें मजेंटा लाइन का जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम मार्ग विस्तार के दो हिस्से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन से दीपाली चौक और मजलिस पार्क से आरके आश्रम मार्ग के साथ ही गोल्डन लाइन के एरोसिटी-तुगलकाबाद कॉरिडोर शामिल है। इनके शुरू होने से मेट्रो के नेटवर्क में लगभग 41 किमी की वृद्धि होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 मार्च, 2019 को मेट्रो के चौथे चरण अंतर्गत मजलिस पार्क-मौजपुर (पिंक लाइन), जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम मार्ग (मजेंटा) और एरोसिटी-तुगलकाबाद (गोल्डन) लाइन को स्वीकृति दी थी।

पहले ग्रीन लाइन अब इसे मजेंटा लाइन में शामिल किया गया: इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 मार्च, 2024 को इसी चरण के अंतर्ग चौथे चरण के अंतर्गत दो और नए कॉरिडोर लाजपत नगर-साकेत जी-ब्लाक (गोल्डन लाइन) और इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ (पहले ग्रीन लाइन अब इसे मजेंटा लाइन में शामिल किया गया है) को स्वीकृति प्रदान की थी। केंद्र से स्वीकृति मिलने के बाद पूर्व की दिल्ली सरकार द्वारा मेट्रो के चौथे चरण के काम को स्वीकृति देने में विलंब व कोरोना महामारी के कारण समय पर काम शुरू नहीं हो सका था। अब इसके निर्माण कार्य में तेजी आई है। पिछले वर्ष जनवरी में जनकपुरी पश्चिम-कृष्ण पार्क एक्सटेंशन पर परिचालन शुरू किया गया था। वहीं, इस वर्ष आठ मार्च को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिंक लाइन के मजलिस पार्क-मौजपुर बाबरपुर कॉरिडोर के साथ ही मजेंटा लाइन के दीपाली चौक से मजलिस पार्क तक के हिस्से का उद्घाटन किया था। मजेंटा लाइन के कृष्णा पार्क से दीपाली चौक और मजलिस पार्क से आरके आश्रम मार्ग तक के हिस्से का निर्माण कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। इससे पूर्वी और पश्चिम दिल्ली की अन्य हिस्सों से मेट्रो कनेक्टिविटी बेहतर होगी। वहीं, गोल्डन लाइन के एरोसिटी- तुगलकाबाद कारिडोर के भी इस वर्ष शुरू होने की बात कही जा रही है।

टीएमसी के 'पुष्पा' का नेपाल में बसने का था प्लान, एसटीएफ ने जहांगीर खान को कैसे धर दबोचा

कोलकाता, एजेंसी। बंगाल स्पेशल टास्क फोर्स और दार्जिलिंग पुलिस ने रविवार दोपहर करीब 2.30 बजे भारत-नेपाल बॉर्डर पर पानीटंकी बाजार से तृणमूल नेता जहांगीर खान को आखिरकार पकड़ ही लिया। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले 'पुष्पा' नाम से मशहूर ये नेता दो हफ्तों से फरार था। जहांगीर खान पर हत्या, रंगदारी और चुनावी गड़बड़ी जैसे कई आपराधिक आरोप थे और कम से कम सात एफआईआर दर्ज थीं। एसटीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जहांगीर खान शुरू में फंसीदेवा के एक होटल में छिपा हुआ था और फिर वह इंटरनेशनल बॉर्डर के पास एक घर में चला गया।

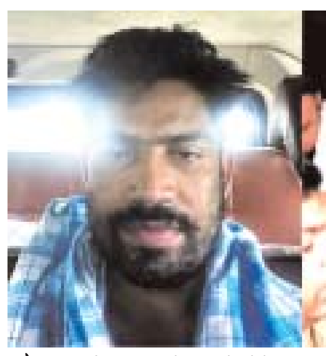

जहांगीर खान ने बनाया था नेपाल में बसने का प्लान: एक और अधिकारी ने बताया कि उसने अपनी पत्नी और बेटे के साथ नेपाल जाने और वहां के स्कूल में अपने बेटे का दाखिला कराने की योजना बनाई थी। इंटेलिजेंस यूनिट के एक अधिकारी ने दावा किया कि खान अकेले ही नेपाल भाग गया था और काठमांडू में एक घर किराए पर लिया था, जहां वह कुछ दिनों तक छिपा रहा। अधिकारी ने बताया कि रविवार सुबह वह पानीटंकी में भारत-नेपाल सीमा के रास्ते भारत लौटा, तभी उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

अंडरग्राउंड हो गया था जहांगीर खान: अधिकारी ने बताया, 'आरोपी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से बचने के लिए पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो गया था। फलता से भागते समय उसने अपने फोन बंद कर दिए, सिम बदल लिए और अपना अकाउंट भी डिलीट कर दिया। लेकिन वह दूसरे तरीकों से अपने कुछ भरोसेमंद साथियों और परिवार के सदस्यों के संपर्क में बना रहा। उन नंबरों को ट्रैक करके और उसके सफर के पैटर्न का पता लगाकर, हमारी टीमों ने उसे ढूंढ निकाला।'

बंगाल एसटीएफ ने क्या कहा

बंगाल एसटीएफ के एक बयान में कहा गया है कि डायमंड हार्बर पुलिस जिले के फलता पुलिस स्टेशन में दर्ज कई मामलों में वांछित खान को रविवार दोपहर करीब 2.30 बजे खारीबारी पुलिस स्टेशन इलाके के पानीटंकी बाजार से गिरफ्तार किया गया। उसको फांसिदेवा पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और राज्य पुलिस व केंद्रीय बलों की एक बड़ी टुकड़ी तैनात की गई। इसके बाद उसे स्थानीय अदालत में पेश किया गया और डायमंड हार्बर पुलिस जिले में लाने का आदेश दिया गया।

दिल्ली-एनसीआर में कब पहुंचेगा मानसून आईएमडी ने दिया ताजा अपडेट; येलो अलर्ट भी जारी

नई दिल्ली। मौसम के बदले मिजाज के बीच तेज धूप में उमस भरी गर्मी एक बार फिर दिल्लीवासियों का हाल बेहाल कर रही है। हीट इंडेक्स तापमान से कहीं ज्यादा दर्ज हो रहा है, तो बिना एसी के राहत नहीं मिल पा रही। कूलर व पंखे बेअसर से हो गए हैं। मौसम विभाग की मानें तो अभी दो दिन और ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ेगा। साफ आसमान और दिन भर खिली रही तेज धूप में सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हालांकि, हीट इंडेक्स 43.2 डिग्री दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक 29.2 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी का स्तर 60 से 22 प्रतिशत दर्ज किया गया। मंगलवार के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आसमान साफ रहेगा। धूप निकली रहेगी। 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 43 और 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बुधवार को भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद बृहस्पतिवार से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम करवट लेगा। तेज हवा के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। इससे तापमान में भी कमी आएगी।

येलो अलर्ट भी जारी किया: बृहस्पतिवार को भी ऐसा ही मौसम रहेगा। दोनों दिनों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून 25 से 30 जून के बीच एनसीआर में पहुंचने की संभावना है। मानसून केरल में चार जून को पहुंचा, जो आमतौर पर एक जून को आता है, यानी उससे तीन दिन बाद।

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बवाल: प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों की झड़प में 11 की मौत, 70 घायल

लाहौर, एजेंसी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जेएएसी कार्यकर्ता की गोलीबारी में मौत के बाद हिंसा भड़क गई। रावलकोट व आसपास में प्रदर्शनकारियों व सुरक्षा बलों में हुई झड़प में 11 लोग मारे गए, जबकि 70 से अधिक लोग घायल हो गए। यह झड़प मंगलवार को जेएएसी की तरफ से प्रस्तावित लॉकडाउन से पहले हुई। पुलिस ने बताया कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) के प्रदर्शनकारी एक अस्पताल की मॉर्चरी के बाहर जमा हुए थे। वहां समूह के एक सदस्य का शव लाया गया था जिसकी मौत पुलिस की फायरिंग में हुई थी। जेएएसी आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए काम करती है, जिस पर पाकिस्तान सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। पुंछ सेक्टर के कमिश्नर सरदार वहीद खान ने बताया, प्रदर्शनकारियों की गोलीबारी में चार पुलिस अधिकारी और एक राहगीर की मौत हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में छह प्रदर्शनकारी मारे गए। पुलिस प्रमुख लियाकत मलिक ने बताया कि रविवार की घटना में 23 सुरक्षाकर्मी और 50 प्रदर्शनकारी घायल हुए थे।

30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जेएएसी ने क्षेत्रीय विधानसभा के लिए 27 जुलाई को होने वाले चुनावों के विरोध में मंगलवार को लॉकडाउन का आह्वान किया है। विधानसभा की 45 में से 12 सीटें शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं जिनका दुरुपयोग किया जाता है। इन सीटों पर स्थानीय लोगों के बजाय पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों के लोगों को नामित कर दिया जाता है।

क्षेत्रीय सरकार ने शुक्रवार को जेएएसी को आतंकरोधी कानून के तहत एक प्रतिबंधित समूह घोषित कर दिया था। सरकार ने घरेलू व विदेशी पर्यटकों को 9 जून से पहले इलाका छोड़ने की सलाह दी है।

प. एशिया: 'न जंग का मैदान छोड़ा, न कूटनीति की मेज , ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियन की अमेरिका-इस्राइल को दो टूक

तेहरान, एजेंसी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने सोमवार को कहा कि उनका देश अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और कूटनीतिक बातचीत जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान किसी भी धमकी के आगे नहीं झुकेगा। लेकिन बातचीत के रास्ते भी खुले रखेगा। राष्ट्रपति पेजेशकियन का यह बयान संघर्ष के 100वें दिन आया है। आठ अप्रैल से ईरान और इस्राइल के बीच लागू अस्थायी युद्धविराम सोमवार को टूट गया, जिससे पश्चिम एशिया एक बार फिर सीधे सैन्य टकराव के गंभीर दौर में पहुंच गया।

पेजेशकियन ने क्या कहा: ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि ईरान की पहली प्राथमिकता देश की सुरक्षा और जनता की भलाई है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता देश की सुरक्षा और जनता में शांति है। उन्होंने कहा कि वह पूरी ताकत के साथ राष्ट्र के अधिकारों की रक्षा करेंगे और किसी भी धमकी के कारण पीछे नहीं हटेंगे। पेजेशकियन ने कहा कि सैन्य तैयारी और कूटनीति दोनों राष्ट्र की ताकत के अहम आधार हैं। उन्होंने इस बात को खारिज किया कि ईरान ने इनमें से किसी एक रास्ते को चुना है।

'न तो जंग का मोर्चा छोड़ा और न ही बातचीत की मेज: उन्होंने कहा, कूटनीति और रक्षा राष्ट्र की ताकत के दो पंख हैं। हमने न तो जंग का मोर्चा छोड़ा है और न ही बातचीत की मेज। पेजेशकियन ने कहा कि राष्ट्रीय एकता और समझदारी भरे फैसलों के जरिये ईरान मौजूदा चुनौतियों से भी पार पा लेगा। उन्होंने कहा, ईश्वर की कृपा से एकता और विवेक के बल पर ईरान इस परीक्षा से भी विजयी होकर निकलेगा।

समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहे इस्राइल-ईरान: ट्रंप: इस बीच, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान और इस्राइल दोनों तत्काल युद्धविराम लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच हाल के दिनों में हुए हमलों और जवाबी हमलों के बाद यह बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा कि पश्चिम एशिया के संघर्ष का स्थायी समाधान निकालने के लिए शांति समझौते पर अंतिम दौर की बातचीत जारी है। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि अज्ञानता या मूर्खता इस समझौते की राह में बाधा बन सकती है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, इस्राइल और ईरान दोनों तत्काल युद्धविराम चाहते हैं।

दुबई में भीषण सड़क हादसा, कई भारतीय श्रमिकों की दर्दनाक मौत; दूतावास बोला- हर संभव करेंगे मदद

दुबई, एजेंसी। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी दुबई में सोमवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना में कई भारतीय श्रमिकों की जान चली गई। यह हादसा उस समय हुआ, जब एक मिनीबस उस ट्रक से जा टकराई जो तकनीकी खराबी के कारण सड़क के बीचोबीच अचानक रुक गया था। इस हादसे में सात लोगों की मौत हुई और नौ अन्य घायल हो गए। दुबई पुलिस के यातायात विभाग के महानिदेशक ब्रिगेडियर जुमा सलेम बिन सुवैदान ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ट्रक तकनीकी खराबी के कारण एमिरेट्स रोड पर अचानक रुक गया था। बस चालक, जिस पर ध्यान न देने और सुरक्षित दूरी बनाए न रखने का आरोप है, ने पीछे से ट्रक में टक्कर मार दी। इस टक्कर के परिणामस्वरूप सात लोगों की मृत्यु हो गई और नौ अन्य घायल हो गए, जिनमें पांच गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया।

भारतीय दूतावास ने हादसे पर जताया शोक: दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'दुबई में हुई दुखद सड़क दुर्घटना से हम बहुत दुखी हैं, जिसमें कई भारतीय श्रमिकों की जान चली गई।' दूतावास ने स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर हर संभव सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए काम करने की बात कही। दूतावास के अधिकारियों ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

हादसे की जांच कर रही दुबई पुलिस: ब्रिगेडियर जुमा सलेम ने बताया कि दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए यातायात दुर्घटना जांच अनुभाग के विशेषज्ञों को घटनास्थल पर भेजा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि यातायात गश्ती दलों ने यातायात को नियंत्रित किया, घटनास्थल को सुरक्षित किया और बचाव वाहनों के प्रवेश की सुविधा प्रदान की। क्षतिग्रस्त ट्रक और बस को हटाकर सामान्य यातायात प्रवाह बहाल कर दिया गया है।

हादसे के बाद दुबई पुलिस ने जारी की चेतावनी: दुबई पुलिस ने वाहन खराब होने, ईंधन खत्म होने या टायर फटने के कारण सड़क के बीच में रुकने के गंभीर खतरों के बारे में चेतावनी दी है। पुलिस ने जोर दिया कि वाहन चालकों को निकलने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका वाहन सड़क पर चलने योग्य है। देश के यातायात कानून के तहत, सड़क के बीच में रुकने पर 1,000 संयुक्त अरब अमीरात दिरहम का जुर्माना और छह ट्रैफिक पॉइंट लगते हैं। इसके साथ ही अनुच्छेद 98 के तहत यातायात बाधित करने पर 500 संयुक्त अरब अमीरात दिरहम का जुर्माना भी लगता है। यातायात विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर जुमा सलेम बिन सुवैदान ने कहा कि सड़क के बीच में रुकना सबसे खतरनाक उल्लंघनों में से एक है, जिससे अक्सर गंभीर दुर्घटनाएं, मौतें और गंभीर चोटें होती हैं। उन्होंने वाहन चालकों से आग्रह किया कि अगर उनका वाहन खराब हो जाता है और उसे हटाया नहीं जा सकता है, तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें।

जनसुनवाई में 477 आवेदकों की समस्याएं सुनी गईं, त्वरित निराकरण के दिए निर्देश

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिला मुख्यालय में मंगलवार को आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक स्तर पर सुनवाई की गई। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने जनसुनवाई में जिले के विभिन्न ग्रामीण, आदिवासी एवं दूरस्थ क्षेत्रों से पहुंचे 477 आवेदकों की शिकायतें, मांगें और समस्याएं सुनीं तथा उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जनसुनवाई के दौरान प्राप्त आवेदनों पर गंभीरता से विचार करते हुए सीईओ जिला पंचायत ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से प्रकरणों की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक आवेदन का समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि नागरिकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने कहा कि जनसुनवाई शासन और जनता के बीच संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके माध्यम से आम नागरिक अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों को केवल औपचारिकता के रूप में न लिया जाए, बल्कि संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ उनका निराकरण किया जाए उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन मामलों के निराकरण के लिए निर्धारित समय-सीमा तय है, उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। साथ ही प्रत्येक आवेदक को उसके आवेदन की प्रगति और की गई कार्रवाई की जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जाए। इससे प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और शासन के प्रति लोगों का विश्वास भी मजबूत होगा जनसुनवाई में राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय, विद्युत, पेयजल, आवास, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य विभागों से संबंधित शिकायतें एवं मांगें प्राप्त हुईं। इन प्रकरणों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए तथा कई मामलों में तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए इस अवसर पर जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे वहीं जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनसुनवाई से जुड़े रहे और प्राप्त आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया की समीक्षा करते रहे प्रशासन का कहना है कि जनसुनवाई के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक आवेदन पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी, ताकि नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो सके और सुशासन की अवधारणा को मजबूत बनाया जा सके।

पशुपालकों ने दूध के लिए नया मूल्य मांगा, भैंस के लिए 70 रुपए प्रति लीटर की मांग

मीडिया ऑडीटर, शहडोल (निप्र)। शहडोल जिले के पशुपालकों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर दूध का उचित मूल्य निर्धारित करने की मांग की उन्होंने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर बताया कि बढ़ती लागत के कारण वर्तमान में दूध की बिक्री से उत्पादन खर्च भी नहीं निकल पा रहा है जिससे दुग्ध व्यवसाय संकट में है पशुपालकों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में पशुओं के चारे, दाना, भूसा, खली और दवाइयों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है इसके साथ ही पशुओं के रखरखाव उपचार और परिवहन पर होने वाला खर्च भी काफी बढ़ गया है इसके बावजूद, दूध की खरीदी 40 से 50 रुपए प्रति लीटर की दर से की जा रही है, जो बढ़ती लागत की तुलना में बहुत कम है। पशुपालकों ने मांग की है कि गाय के दूध का न्यूनतम मूल्य 60 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध का मूल्य 70 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया जाए किसानों ने ज्ञापन में यह भी बताया कि पिछले पांच वर्षों से दूध की गुणवत्ता के आधार पर खोवा का मूल्य 0.25 रुपए निर्धारित है जो अब व्यवहारिक नहीं है उन्होंने गुणवत्ता आधारित खोवा मूल्य को बढ़ाकर 0.27 रुपए करने की भी मांग की पशुपालकों ने चेतावनी दी कि यदि दूध का उचित मूल्य तय नहीं किया गया तो बड़ी संख्या में लोग दुग्ध व्यवसाय छोड़ने को मजबूर हो सकते हैं जिसका सीधा असर दूध उत्पादन पर पड़ेगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान राजेश यादव, संतलाल महेश सहित कई पशुपालक मौजूद रहे। उन्होंने प्रशासन से उनकी मांगों पर शीघ्र विचार कर निर्णय लेने की अपेक्षा जताई है।

स्व सहायता समूहों को मिलेगा बढ़ावा, विद्यालयों में स्थानीय उत्पादों की खरीदी के निर्देश

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। कलेक्टर विकास मिश्रा ने जिले में संचालित स्व सहायता समूहों की आजीविका को सशक्त बनाने तथा उनके उत्पादों के लिए स्थायी बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिले के समस्त शासकीय आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में उपयोग होने वाली सामग्री, वस्तुओं एवं सेवाओं का उपार्जन नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय स्व सहायता समूहों के माध्यम से किया जाए कलेक्टर मिश्रा ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जिले के सभी विकासखंडों में गठित स्व सहायता समूहों द्वारा विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है। शासन की 'वोकल फॉर लोकल' नीति के अनुरूप इन उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने और समूहों की विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर निर्मित उत्पादों की खरीदी से एक ओर स्व सहायता समूहों की महिलाओं की आय में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के स्थायी अवसर भी विकसित होंगे। इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन,युवा कांग्रेस ने मुख्य अभियंता से की शिकायत, बिना सूचना कटौती पर रोक लगाने की मांग

मीडिया ऑडीटर, शहडोल (निप्र)। शहडोल जिले में अघोषित बिजली कटौती और विद्युत विभाग की कथित अव्यवस्थाओं के विरोध में मंगलवार को युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया प्रदेश सचिव अभिषेक शुक्ला के नेतृत्व में कार्यकर्ता मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के मुख्य अभियंता कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा।

बिना सूचना बिजली कटौती का आरोप: युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जिले में सुबह, दोपहर और शाम को बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली आपूर्ति बाधित की जा रही है इससे आम नागरिकों, व्यापारियों विद्यार्थियों और किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है भीषण गर्मी के बीच लगातार हो रही कटौती से जनजीवन प्रभावित होने की बात कही गई संगठन ने मांग की कि अघोषित बिजली कटौती पर रोक लगाई जाए और किसी भी आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को पहले से सूचना दी जाए।

ट्रांसफार्मर और मेंटेनेंस पर उठे सवाल: ज्ञापन में विद्युत विभाग पर ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पर कथित कमीशनखोरी के आरोप भी लगाए गए हैं। युवा कांग्रेस ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि मेंटेनेंस के नाम पर बार-बार बिजली बंद की जाती है, लेकिन व्यवस्था में सुधार नहीं दिखता। साथ ही वर्षा ऋतु से पहले जर्जर विद्युत लाइनों और उपकरणों की मरम्मत की मांग की गई आंदोलन की चेतावनी युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो संगठन जनहित में बड़ा आंदोलन करेगा। प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष अनुपम गौतम सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

अस्पतालों में समय पर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश, ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर होगी कार्रवाई

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने सभी शासकीय चिकित्सालयों के चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को निर्धारित समय पर अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित रहकर सेवाएं प्रदान करने के निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश कलेक्टर विकास मिश्रा द्वारा समय-सीमा बैठक में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जारी किए गए हैं जारी आदेश के अनुसार जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) तथा आपातकालीन कक्ष में रोस्टर के अनुसार चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। ओपीडी में उपचार हेतु रोगियों के पर्चे प्रातः 8.45 बजे से दोपहर 1.45 बजे तक तथा सायंकाल 4.45 बजे से 5.45 बजे तक बनाए जाएंग ओपीडी में मरीजों के उपचार का समय प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक एवं सायंकाल 5 बजे से 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। वहीं भर्ती मरीजों की जांच के लिए चिकित्सकों को प्रतिदिन दो बार वार्ड राउंड लेने के निर्देश दिए गए हैं।

सड़क-नालियों का अधिकारियों ने किया निरीक्षण,अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त 7 दिन में कब्जा नहीं हटने पर चलेगा बुलडोजर

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। मझौली जनपद पंचायत के मड़वास में सड़क और नालियों पर बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। मंगलवार दोपहर तहसीलदार और एसडीएम सहित कई विभागों के अधिकारियों ने मड़वास पहुंचकर अतिक्रमण का निरीक्षण किया। अतिक्रमणकारियों को सात दिन के भीतर स्वयं कब्जा हटाने की चेतावनी दी गई है, ऐसा न करने पर बुलडोजर चलाने की बात कही गई है मड़वास में हल्की बारिश में भी मुख्य सड़क जलमग्न हो जाती है। इसका मुख्य कारण सड़क और नालियों पर अतिक्रमण है, जिससे पानी की निकासी बाधित होती है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे एक बैठक आयोजित की गई।

अधिकारियों ने सड़क और नालियों का निरीक्षण किया: बैठक के बाद अधिकारियों ने मौके पर जाकर सड़क और नालियों का निरीक्षण किया और स्थानीय दुकानदारों व निवासियों से चर्चा की। तहसीलदार राजेश पारस ने बताया कि लगभग 21 लोगों को अतिक्रमण हटाने की समझाइश दी गई है उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे सात दिन के भीतर स्वयं अपना कब्जा हटा लें। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित समय-सीमा में अतिक्रमण न हटाने पर प्रशासन वैधानिक कार्रवाई करते हुए बलपूर्वक कब्जा हटाएगा।

दुकानदारों को भी अपनी निर्धारित सीमा में ही सामान रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि यातायात सुचारु रहे और नालियों की सफाई व जल निकासी व्यवस्था बाधित न हो। प्रशासन का मानना है कि अतिक्रमण हटने से बरसात में होने वाले जलभराव से काफी राहत मिलेगी और लोगों को आवागमन में सुविधा होगी इस निरीक्षण और कार्रवाई के दौरान पीडब्ल्यूडी विभाग की एसडीओ शुभी गौतम, जनपद पंचायत मझौली की मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) सुरभि श्रीवास्तव और तहसीलदार मड़वास राजेश पारस सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रशासन ने नागरिकों से सार्वजनिक मार्गों और नालियों को अतिक्रमण मुक्त रखने में सहयोग की अपील की है।

अस्पताल में गार्ड ने लगाए इंजेक्शन: स्टाफ नर्स सब मैप को नोटिस, दो दिन में रिपोर्ट मांगी

मीडिया ऑडीटर,सिंगरौली (निप्र)। चितरंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में सुरक्षा गार्ड द्वारा मरीजों को इंजेक्शन लगाने और ड्रिप चढ़ाने का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. पुष्पराज सिंह ने मंगलवार को अस्पताल की स्टाफ नर्स और सब मैप (स्वास्थ्य कर्मचारी) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है डॉ. पुष्पराज सिंह ने बताया कि मामले की जांच के लिए जिला स्तर पर एक समिति गठित की गई है इस समिति को दो दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदार कर्मचारियों

के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी सीएमएचओ के अनुसार प्रारंभिक जांच में सुरक्षा गार्ड की लापरवाही सामने आई है उन्होंने स्पष्ट किया कि मरीजों को दवा देना इंजेक्शन लगाना और ड्रिप चढ़ाना प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों का ही कार्य है गार्ड द्वारा यह कार्य किया जाना एक गंभीर अनियमितता है प्राथमिक तौर पर गार्ड के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।

नर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी: डॉ. सिंह ने यह भी बताया कि घटना के समय ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स की जिम्मेदारी मरीजों की देखरेख और उपचार व्यवस्था सुनिश्चित करने की थी इसलिए संबंधित नर्स के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी हालांकि, सीएमएचओ ने अस्पताल में पदस्थ चिकित्सक की भूमिका पर अभी कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की है उन्होंने कहा कि जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही किसी की जवाबदेही तय की जाएगी गौरतलब है कि वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए थे उन्होंने उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं।

वृद्धाश्रम में निवासरत बुजुर्गों को श्रवण यंत्र एवं फिजियोथेरेपी सेवाओं का लाभ

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देशन एवं उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण धनंजय मिश्रा के मार्गदर्शन में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र द्वारा पनवार स्थित वृद्धाश्रम में निवासरत वृद्धजनों के लिए विशेष स्वास्थ्य एवं सहायता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बुजुर्गों को श्रवण यंत्र उपलब्ध कराए गए तथा फिजियोथेरेपी सेवाएं प्रदान की गईं, जिससे उनके चेहरों पर लंबे समय बाद मुस्कान लौट आई कार्यक्रम के दौरान वृद्धाश्रम में निवासरत सोमनाथ जायसवाल, जयकरण बैगा एवं कुमरिया कोरी को श्रवण यंत्र (कान की मशीन) प्रदान किए गए।

समान नागरिक संहिता पर सीधी में व्यापक जनसंवाद, विभिन्न वर्गों ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव

विवाह, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, भरण-पोषण एवं लिव-इन रिलेशनशिप जैसे विषयों पर हुई विस्तृत

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) के संभावित क्रियान्वयन के संबंध में नागरिकों के सुझाव एवं विचार प्राप्त करने के उद्देश्य से मंगलवार को शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-1, सीधी के स्वामी विवेकानंद सभागार में जन-परामर्श बैठक आयोजित की गई। उच्च स्तरीय समिति के सदस्य अनूप नायर की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, शांति समिति के सदस्यों, प्रबुद्ध नागरिकों तथा समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया बैठक के दौरान समान नागरिक संहिता के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की गई। इसमें विवाह, विवाह विच्छेद एवं भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण तथा लिव-इन रिलेशनशिप जैसे विषय प्रमुख रूप से शामिल रहे। उपस्थित प्रतिभागियों ने अपने अनुभवों, सुझावों और शंकाओं को खुलकर साझा किया तथा विषय के सामाजिक, कानूनी एवं व्यावहारिक पहलुओं पर महत्वपूर्ण विचार रखे प्रतिभागियों ने सुझाव दिया कि किसी भी नए कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व्यापक जन-जागरूकता आवश्यक है। साथ ही समाज के सभी वर्गों के साथ निरंतर संवाद स्थापित कर उनकी भावनाओं और अपेक्षाओं को समझना भी जरूरी है। कई वक्ताओं ने कानूनी प्रक्रियाओं को सरल एवं सुगम बनाने तथा आम नागरिकों तक सही जानकारी पहुंचाने पर विशेष बल दिया उच्च स्तरीय समिति के सदस्य अनूप नायर ने कहा कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा समान नागरिक संहिता के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन एवं परीक्षण के लिए समिति का गठन किया गया है। समिति का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों, समुदायों और हितधारकों के सुझाव एवं विचार प्राप्त कर एक समग्र एवं संतुलित दृष्टिकोण विकसित करना है। उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद-44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है तथा इसी संदर्भ में प्रदेशभर में जन-परामर्श की प्रक्रिया संचालित की जा रही है उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने सुझाव एवं विचार अधिक से अधिक संख्या में साझा करें। बैठक में प्राप्त सुझावों को संकलित कर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे भविष्य की कार्यवाही में जनभावनाओं और सामाजिक अपेक्षाओं का समुचित समावेश सुनिश्चित किया जा सके उन्होंने बताया कि वे अपने सुझाव एवं विचार ऑनलाइन माध्यम से भी दर्ज करा सकते हैं इसके लिए राज्य शासन द्वारा विकसित पोर्टल नबबण्उचणहवअण्पद उपलब्ध है, जहां आमजन अपनी राय प्रस्तुत कर सकते हैं यह जन-परामर्श बैठक समान नागरिक संहिता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर समाज के विभिन्न वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा लोकतांत्रिक संवाद को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई।

कलेक्टर के संवेदनशील हस्तक्षेप से वृद्ध पिता को मिला सम्मान और सहारा

80 वर्षीय चंद्रभान साहू के भरण-पोषण की जिम्मेदारी पुत्रों को सौंपने का आदेश, परिवार में फिर लौटी अपनत्व की भावना

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। प्रशासन की संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण का एक प्रेरक उदाहरण उस समय देखने को मिला, जब कलेक्टर विकास मिश्रा के पटपरा क्षेत्र भ्रमण के दौरान 80 वर्षीय वृद्ध चंद्रभान साहू ने अपनी पीड़ा साझा की। जीवन के इस अंतिम पड़ाव में, जब उन्हें अपने परिवार के सहयोग और सहारे की आवश्यकता थी, तब वे भोजन, दवा और दैनिक आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करने को विवश थे। अपनी चल-अचल संपत्ति पुत्रों के नाम कर देने के बाद भी उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा था और वे अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवनयापन कर रहे थे वृद्धजन की समस्या सुनते ही कलेक्टर विकास मिश्रा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उनके निर्देशन में उपखंड अधिकारी (राजस्व) विकास आनंद द्वारा माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत प्रकरण दर्ज कर सुनवाई की गई जांच और सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि चंद्रभान साहू ने अपने जीवनकाल में ही अपनी चल एवं अचल संपत्तियों का बंटवारा पुत्रों के बीच कर दिया था। इसके बावजूद उनके भरण-पोषण और देखभाल की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। प्रशासन द्वारा मामले का गंभीरता से परीक्षण कर सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायोचित निर्णय लिया गया न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए चंद्रभान साहू के सभी पुत्रों को अपने पिता के भरण-पोषण के लिए प्रत्येक माह एक-एक हजार रुपये प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। यह राशि प्रत्येक माह की 1 से 5 तारीख के मध्य अनिवार्य रूप से दी जाएगी, जिससे वृद्धजन की भोजन, दवा एवं अन्य आवश्यक जरूरतों की पूर्ति सुनिश्चित हो सके सुनवाई के दौरान एक सकारात्मक पहलू यह भी सामने आया कि परिवार के सदस्यों के बीच सहमति बनी और चंद्रभान साहू अपने बड़े पुत्र के साथ पैतृक घर में रहने के लिए तैयार हुए। सभी पुत्रों ने उनकी देखभाल, भोजन एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन

एक थोपे युद्ध के 100 दिन

संपादकीय

ईरान युद्ध के 100 दिन बीत चुके हैं। अब यह अनचाहा युद्ध बनता जा रहा है। न तो अमरीका जीत का दावा कर सकता है और न ही ईरान को आत्मसमर्पण के लिए विवश किया जा सका है। उसके भी विनाशक पलटवार जारी हैं। यह ऐसा युद्ध है, जिससे अमरीका और ईरान अब बाहर निकलना और एक साझा समझौता करना चाहते हैं, लेकिन जिद और महत्वाकांक्षाएं रोड़े अटका रही हैं। यह ऐसा युद्ध है, जिसने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को हिला कर रख दिया है, महामंदी के आकलन किए जा रहे हैं, 146 देशों में तेल-गैस-खाद के संकट गहराते जा रहे हैं और समुद्री सप्लाई चेन का एक महत्वपूर्ण मार्ग लगभग बंद है। नतीजतन विश्व आर्थिकी को 474 लाख करोड़ रुपए की चोट लग चुकी है। यह विभिन्न एजेंसियों के आकलन के निष्कर्ष हैं। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) ने चेताया है कि यदि ऊर्जा-बाधा और संकट जारी रहे, तो वैश्विक जीडीपी और रोजगार को गंभीर झटके लगेंगे। विश्व बैंक और आईएमएफ के आकलन पहले ही सामने आ चुके हैं कि वैश्विक जीडीपी की विकास दर 2 फीसदी तक लुढ़क सकती है। बीते 80 साल में, लगभग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यह पहला युद्ध है, जिसमें 14 देश प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से जुड़े हैं। यह युद्ध ऐसा रहा है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या कर दी गई। होर्मुज जलडमरूमध्य मार्ग पहली बार बंद हुआ है। खामेनेई समेत करीब 50 लाख के ऐप हैक किए जा चुके हैं। युद्ध में करीब 7000 लोग मारे जा चुके हैं और करीब 55,000 घायल बताए गए हैं। ईरान के करीब 32 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। लेबनान में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित बताए गए हैं। ऐसा नहीं है कि अमरीका और इजरायल के नुकसान नहीं हुए हैं। अमरीका के सैन्य खर्च, महंगाई और अप्रत्यक्ष प्रभाव आदि पर 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक की चपत लग चुकी है। आज अमरीका पर 39 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, जबकि उसकी कुल अर्थव्यवस्था 32 ट्रिलियन डॉलर से कुछ अधिक की है। ईरान के जीडीपी और बुनियादी ढांचे को लेकर 28.5 लाख करोड़ रुपए और खाड़ी देशों को ऊर्जा-ढांचों को ध्वस्त करने या जला देने के कारण 5.54 लाख करोड़ रुपए के नुकसान आंके गए हैं। वैश्विक जीडीपी पर 339 लाख करोड़ रुपए का भारी नुकसान माना जा रहा है।

इन नुकसानों और विपरीत, ढहती आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद और 100 दिनों के टकराव, तनाव के बाद भी युद्ध खत्म होने के आसार दिख नहीं रहे हैं। बेशक बीते 60 दिनों से युद्धविराम का ढोंग किया जा रहा है, लेकिन युद्ध रुक-रुक कर जारी रहा है। मिसाइल, ड्रोन के हमले जारी हैं, हवाई हमले भी किए जा रहे हैं, कहीं विस्फोट है, तो कहीं आग की ऊंची-ऊंची लपटों के साथ धुएं के गहरे गुबार हैं।

1948 के राजनीति की झलक 2026 में

सनत जैन

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो अभिनेता से नेता बने थलापति विजय ने तमिलनाडु की राजनीति में नई शुरुआत की है। 1948 से 1952 में जिस तरह की राजनीति देश में हो रही थी, उसकी यादों को ताजा कर रही है। तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवीके को कांग्रेस ने समर्थन दिया है। तमिलनाडु सरकार में कांग्रेस पार्टी का एक मंत्री भी है। तमिलनाडु में कांग्रेस का कोई विशेष वर्चस्व नहीं है। केंद्रीय राजनीति में कांग्रेस एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। आज भी कांग्रेस पार्टी का सीधा मुकाबला 300 लोकसभा सीटों पर भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों के साथ होता है। वर्तमान की राजनीति में जिस तरह से राजनीतिक दलों के बीच में वैमनष्य देखने को मिलता है, जिस तरह की असुरक्षा की भावना देखने को मिलती है। सत्ता में ज्यादा से ज्यादा सहभागिता मिले इसके लिए राजनीतिक दल हर संभव प्रयास करते हैं इसके विपरीत तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने राज्यसभा की दो सीटें सहयोगी दल कांग्रेस को देने का फैसला किया है। उनका मानना है, उनकी पार्टी केंद्र की राजनीति में कांग्रेस के साथ सहयोग करके तमिलनाडु के हितों का संरक्षण ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकती है। दो सांसद उनकी पार्टी के राज्यसभा में चले भी गए, तो वह तमिलनाडु का पक्ष सशक्त तरीके से नहीं रख सकते हैं जितने सशक्त तरीके से कांग्रेस उनकी लड़ाई केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा में लड़ सकती है। गठबंधन की राजनीति में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का यह निर्णय, स्वतंत्रता के पश्चात अनूठा है। जब संविधान सभा और केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्माण हो रहा था, उस समय कांग्रेस पार्टी ने सभी समुदाय और सभी राजनीतिक दलों के लोगों को संविधान सभा और मंत्रिमंडल में स्थान देकर मजबूत संविधान और मजबूत सरकार बनाने का काम किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल में अपने विरोधी और अन्य विचारधारा के लोगों को भी शामिल करके स्वतंत्रता के पश्चात समन्वय की राजनीति का मार्ग अपनाया था। वही मार्ग 2026 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा अपनाया गया है। वर्तमान मंर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के रूप में देश के अधिकांश राजनीतिक दल गठबंधन की राजनीति में शामिल हैं। क्षेत्रीय दल एक-एक सीट के लिए अपनी मजबूत दावेदारी रखते हैं। ऐसी स्थिति में तमिलनाडु की राजनीति में मुख्यमंत्री थलापति विजय ने कांग्रेस को राज्यसभा की रिक्त दो सीटें देकर गठबंधन की राजनीति को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। राज्य की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्षेत्रीय राजनीति में भाषा संस्कृति तथा आम जनता के साथ उनका जुड़ाव गहरा होता है। लेकिन केंद्रीय राजनीति में राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को निर्णय करने पड़ते हैं। संघीय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्यों के बीच संबंध बेहतर हों। पिछले एक दशक में इस स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। मोदी सरकार के अस्तित्व में आते ही योजना मंडल को भंग कर दिया गया था। उसके स्थान पर नीति आयोग बनाया गया, नीति आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है। उसके बाद से राज्य सरकारें आरोप लगाती रही हैं, केंद्र सरकार उनके साथ न्याय नहीं कर रही है। मनमाने तरीके से संसाधन और धन का बंटवारा किया जा रहा है। जिन राज्यों में गैर भाजपा की सरकारें हैं उनके साथ भेदभाव की शिकायत बढ़ती चली जा रही है। जिस तरह से जाति और धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है, उसमें राज्यों के साथ केंद्र सरकार की दूरियां बढ़ रही है। रही सही कसर राज्यपालों ने पूरी कर दी है। राज्य विधानसभा द्वारा लिए गए निर्णय और कानूनों का पालन राज्यपाल नहीं होने देते हैं। एक समानांतर सत्ता राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में गैर भाजपाई शासित राज्यों में देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भारतीय राजनीति में एक बार फिर दशकों पुरानी राजनीति को स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। अपने सहयोगी दल कांग्रेस, जो केंद्र में एक प्रभावी भूमिका में है, उस पार्टी को राज्यसभा की 2 रिक्त सीट देकर, स्वार्थ की राजनीति से इतर विश्वास का नया मार्ग चुना है। उसकी सारे देश में अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। क्षेत्रीय दल 1990 के दशक के बाद से महत्वपूर्ण भूमिका में आये हुए हैं।

विकास का इंजन, पर असुरक्षित मध्यम वर्ग

'मिसिंग मिडिल' की चुनौती और आर्थिक सुरक्षा का प्रश्न भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वैश्विक मंच पर उसकी बढ़ती आर्थिक शक्ति, विशाल युवा आबादी, डिजिटल क्रांति और बढ़ते उपभोक्ता बाजार की चर्चा लगातार हो रही है। इस विकास यात्रा के केंद्र में यदि कोई सामाजिक-आर्थिक वर्ग सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तो वह है भारत का मध्यम वर्ग। यही वर्ग देश में उपभोग बढ़ाता है, बचत करता है, निवेश करता है, कर देता है, शिक्षा और कौशल में निवेश करता है तथा आर्थिक गतिविधियों को निरंतर गति प्रदान करता है। किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था में मध्यम वर्ग को विकास का इंजन माना जाता है क्योंकि उसकी आय और आकांक्षाएं उत्पादन तथा बाजार दोनों को संचालित करती हैं। भारत में भी मध्यम वर्ग को भविष्य के आर्थिक विकास, सामाजिक स्थिरता और लोकतांत्रिक मजबूती का आधार माना जाता है। इसके बावजूद एक विडंबना यह है कि भारतीय मध्यम वर्ग का बड़ा हिस्सा स्वयं आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं है।

डॉ. प्रियंका सौरभ

वह गरीबी से ऊपर तो उठ चुका है, लेकिन स्थायी समृद्धि और सुरक्षा तक नहीं पहुंच पाया है। यही स्थिति अर्थशास्त्र में मिसिंग मिडिल अर्थात लुप्त या कमजोर मध्य वर्ग की परिघटना के रूप में पहचानी जाती है।

'मिसिंग मिडिल' का आशय उस स्थिति से है जिसमें समाज में गरीबों और अमीरों के बीच स्थित मध्यम वर्ग पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं होता या उसकी आर्थिक स्थिति इतनी स्थिर नहीं होती कि वह किसी संकट का सामना कर सके। भारत में लाखों परिवार ऐसे हैं जो आय के आधार पर मध्यम वर्ग में गिने जाते हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त बचत, सामाजिक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच या दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता नहीं होती। परिणामस्वरूप वे किसी बीमारी, नौकरी जाने, व्यवसाय में नुकसान या आर्थिक मंदी जैसी परिस्थितियों में तेजी से आर्थिक संकट में फंस सकते हैं। कोविड-19 महामारी ने इस वास्तविकता को बहुत स्पष्ट रूप से सामने ला दिया था। महामारी के दौरान लाखों ऐसे परिवार, जो स्वयं को मध्यम वर्ग का हिस्सा मानते थे, अचानक आय के स्रोत समाप्त होने, चिकित्सा खर्च बढ़ने और रोजगार अस्थिर होने के कारण आर्थिक कठिनाइयों में आ गए। इससे यह स्पष्ट हुआ कि भारत का मध्यम वर्ग संख्या में बड़ा होने के बावजूद सुरक्षा के मामले में कमजोर है।

भारतीय मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी शक्ति उसकी उपभोग क्षमता है। देश में घर, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, पर्यटन और डिजिटल सेवाओं की मांग का बड़ा हिस्सा इसी वर्ग से आता है। जब मध्यम वर्ग की आय बढ़ती है तो वह अधिक वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करता है, जिससे उद्योगों का विस्तार होता है, निवेश बढ़ता है और नए रोजगार सृजित होते हैं। यही कारण है कि विकसित देशों की आर्थिक सफलता के पीछे मजबूत मध्यम वर्ग को एक प्रमुख कारक माना जाता है। भारत भी यदि विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे अपने मध्यम वर्ग को अधिक मजबूत और सुरक्षित बनाना होगा। लेकिन वर्तमान में यह वर्ग कई प्रकार की चुनौतियों से घिरा हुआ है।

सबसे पहली चुनौती रोजगार की गुणवत्ता और स्थिरता से जुड़ी है। भारत में रोजगार का एक बड़ा हिस्सा अभी भी असंगठित क्षेत्र में है। यहां कार्यरत लोगों को नियमित वेतन, भविष्य निधि, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा या अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिलते। शिक्षित युवाओं की बड़ी संख्या भी ऐसी नौकरियों में काम कर रही है जो उनकी योग्यता के अनुरूप नहीं हैं। रोजगार के अवसर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें से कई अस्थायी, संविदा आधारित या कम वेतन वाले हैं। गिग अर्थव्यवस्था और प्लेटफॉर्म आधारित रोजगार ने नए अवसर तो पैदा किए हैं, लेकिन उनमें भी दीर्घकालिक सुरक्षा का अभाव है। ऐसे में मध्यम वर्ग के लिए भविष्य की आर्थिक योजना बनाना कठिन हो जाता है।

दूसरी बड़ी चुनौती स्वास्थ्य और शिक्षा के बढ़ते खर्च की है। भारत में गुणवत्तापूर्ण सरकारी स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं की सीमित उपलब्धता के कारण मध्यम वर्ग को निजी संस्थानों पर निर्भर रहना पड़ता है। बच्चों की शिक्षा, कोचिंग, उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाला व्यय परिवारों की आय का बड़ा हिस्सा खा जाता है। किसी गंभीर बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में वर्षों की बचत समाप्त हो सकती है। अनेक अध्ययन बताते हैं कि भारत में स्वास्थ्य पर होने वाला व्यक्तिगत खर्च आज भी काफी अधिक है। यह स्थिति मध्यम वर्ग को आर्थिक रूप से असुरक्षित बनाती है और उसे लगातार वित्तीय दबाव में रखती है।

तीसरी चुनौती महंगाई और जीवन-यापन की बढ़ती लागत है। महानगरों और बड़े शहरों में आवास, परिवहन, ऊर्जा, भोजन और अन्य आवश्यक सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है। हालांकि आय में भी वृद्धि होती है, लेकिन कई बार वह महंगाई की गति के अनुरूप नहीं होती। परिणामस्वरूप वास्तविक आय और क्रय शक्ति प्रभावित होती है। मध्यम वर्ग को अपने जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए अधिक ऋण लेना पड़ता है। गृह ऋण, वाहन ऋण, शिक्षा ऋण और उपभोक्ता ऋणों का बढ़ता बोझ भी वित्तीय असुरक्षा को बढ़ाता है।

'मिसिंग मिडिल' की समस्या का एक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भारत में गरीबों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं उपलब्ध हैं, जैसे मुफ्त राशन, स्वास्थ्य बीमा, आवास सहायता और अन्य सामाजिक लाभ। दूसरी ओर उच्च आय वर्ग के पास निजी संसाधन और निवेश होते हैं, जिनसे वे जोखिमों का सामना कर सकते हैं। लेकिन मध्यम वर्ग अक्सर इन दोनों के बीच फंस जाता है। वह सरकारी सहायता योजनाओं के लिए पात्र नहीं होता, जबकि निजी सुरक्षा और सेवाओं की पूरी लागत वहन करना भी उसके लिए कठिन होता है। यही कारण है कि किसी भी अप्रत्याशित संकट की स्थिति में वह तेजी से आर्थिक अस्थिरता की ओर बढ़ सकता है।

भारत में छोटे और मध्यम उद्यमों की सीमित वृद्धि भी 'मिसिंग मिडिल' की समस्या को बढ़ाती है। छोटे व्यवसाय अक्सर वित्त, तकनीक और बाजार तक पर्याप्त पहुंच के अभाव में बड़े नहीं बन पाते। परिणामस्वरूप वे बड़ी संख्या में उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार उत्पन्न नहीं कर पाते। यदि छोटे और मध्यम उद्यम मजबूत हों तो वे रोजगार सृजन और आय वृद्धि के माध्यम से मध्यम वर्ग का विस्तार कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में अनेक उद्यम नियामकीय जटिलताओं, पूंजी की कमी और प्रतिस्पर्धात्मक दबावों से जूझ रहे हैं।

मध्यम वर्ग की एक और चुनौती है संपत्ति निर्माण की सीमित क्षमता। विकसित देशों में मध्यम वर्ग के पास आवास, पेंशन फंड, निवेश पोर्टफोलियो और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां होती हैं, जो उन्हें दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। भारत में बड़ी संख्या में मध्यमवर्गीय परिवारों की बचत सीमित होती है और उनका अधिकांश संसाधन दैनिक खर्चों तथा बच्चों के भविष्य पर केंद्रित रहता है। इससे वे पर्याप्त संपत्ति निर्माण नहीं कर पाते। वित्तीय बाजारों में भागीदारी बढ़ने के बावजूद अभी भी बड़ी संख्या में लोग दीर्घकालिक निवेश के प्रति जागरूक नहीं हैं।

भारत के मध्यम वर्ग को एक मजबूत और लचीली आर्थिक शक्ति में बदलने के लिए बहुआयामी नीति हस्तक्षेप आवश्यक हैं। सबसे पहले गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन को राष्ट्रीय विकास रणनीति का केंद्र बनाया जाना चाहिए। विनिर्माण क्षेत्र, हरित ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और आधुनिक सेवा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा किए जाने चाहिए। रोजगार केवल संख्या में नहीं, बल्कि गुणवत्ता और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बेहतर होने चाहिए। श्रम बाजार में कौशल विकास और पुनः कौशल विकास कार्यक्रमों को भी मजबूत किया जाना चाहिए ताकि बदलती तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यबल तैयार हो सके।

दूसरा महत्वपूर्ण कदम स्वास्थ्य और शिक्षा में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना है। यदि नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सरकारी विद्यालय, विश्वविद्यालय और अस्पताल उपलब्ध होंगे तो मध्यम वर्ग पर निजी खर्च का बोझ कम होगा। इससे उनकी बचत और निवेश क्षमता बढ़ेगी तथा आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी। शिक्षा और स्वास्थ्य केवल सामाजिक सेवाएं नहीं हैं, बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास के आधार भी हैं। तीसरा, सामाजिक सुरक्षा के दायरे को व्यापक बनाया जाना चाहिए। असंगठित क्षेत्र, गिग अर्थव्यवस्था और स्वरोजगार से जुड़े लोगों के लिए पेंशन, बीमा और आय सुरक्षा योजनाओं का विस्तार आवश्यक है। सामाजिक सुरक्षा को केवल गरीबों तक सीमित रखने के बजाय व्यापक मध्यम वर्ग तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इससे आर्थिक झटकों के समय परिवारों को सुरक्षा मिलेगी और वे पुनः गरीबी में गिरने से बच सकेंगे।

चौथा, किफायती आवास और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना चाहिए। मध्यम वर्ग के लिए घर का स्वामित्व आर्थिक स्थिरता का महत्वपूर्ण आधार है। सरकार और वित्तीय संस्थानों को ऐसी नीतियां विकसित करनी चाहिए जो मध्यम आय वर्ग को सस्ती दरों पर आवास ऋण और अन्य वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। साथ ही निवेश और बचत को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं को और अधिक आकर्षक बनाया जाना चाहिए।

पांचवां, छोटे और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने की दिशा में विशेष प्रयास होने चाहिए। वित्तीय सहायता, तकनीकी उन्नयन, डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच और निर्यात अवसरों को बढ़ाकर इन उद्यमों को विकास का नया आधार बनाया जा सकता है। जब ये उद्यम बढ़ेंगे तो गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजित होंगे और मध्यम वर्ग का विस्तार होगा।

छठा, कर प्रणाली को अधिक संतुलित और न्यायसंगत बनाना आवश्यक है। मध्यम वर्ग पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के प्रभाव का समुचित मूल्यांकन करते हुए ऐसी नीतियां बनाई जानी चाहिए जो उनकी क्रय शक्ति को मजबूत करें। कर संग्रह और सामाजिक सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करना समय की मांग है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि भारत का मध्यम वर्ग केवल एक आर्थिक श्रेणी नहीं, बल्कि देश की विकास यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक आधार है। यह वर्ग उपभोग, निवेश, नवाचार और सामाजिक स्थिरता का वाहक है। किंतु 'मिसिंग मिडिल' की परिघटना के कारण इसका बड़ा हिस्सा आर्थिक रूप से असुरक्षित बना हुआ है। यदि भारत को दीर्घकालिक और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है तो उसे अपने मध्यम वर्ग को केवल संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि सुरक्षा, अवसर और संपन्नता के आधार पर भी मजबूत बनाना होगा। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और उद्यमिता को केंद्र में रखकर बनाई गई नीतियां ही इस वर्ग को एक सशक्त और लचीली आर्थिक शक्ति में बदल सकती हैं। जब भारत का मध्यम वर्ग वास्तव में सुरक्षित, आत्मनिर्भर और समृद्ध होगा, तभी देश की विकास गाथा अधिक टिकाऊ, समावेशी और व्यापक बन सकेगी।

ईरान-इजराइल संघर्ष विराम का टूटना: तेल कीमतों में उछाल, व्यापारिक अनिश्चितता

क्षेत्रीय अस्थिरता और महायुद्ध की आशंकाएं, विश्व शांति, मध्य पूर्व की स्थिरता के लिए बढ़ता खत

ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता सैन्य टकराव विश्व शांति, वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और मानवीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बन सकता है विश्व शांति की रक्षा, आर्थिक स्थिरता की सुरक्षा और मानवता के हित में युद्ध नहीं बल्कि कूटनीति ही सबसे प्रभावी मार्ग सिद्ध हो सकती है वैश्विक स्तरपर मध्य पूर्व एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है जहां किसी भी छोटी चिंगारी से व्यापक क्षेत्रीय युद्ध की आग भड़क सकती है। अप्रैल 2026 से लागू अस्थायी संघर्ष विराम (सीजफायर) के बावजूद ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बना हुआ था, किंतु 8 जून 2026 को दोनों देशों के बीचप्रत्यक्ष मिसाइल और हवाई हमलों ने यह संकेत दे दिया कि संघर्ष विराम गंभीर संकट में पड़ गया है।

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं)

विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जबकि इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में ईरान के कई सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर हवाई हमले किए। इससे पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ गई है और दुनिया को एक बार फिर बड़े युद्ध की आशंका सताने लगी है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क़ि यह संघर्ष केवल दो देशों के बीच सैन्य टकराव भर नहीं है, बल्कि इसके पीछे भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय प्रभाव की लड़ाई, सुरक्षा चिंताएं, परमाणु कार्यक्रमों को लेकर अविश्वास और अनेक प्रॉक्सी संगठनों की भूमिका भी जुड़ी हुई है।पिछले कुछ वर्षों में ईरान और इजराइल के बीच प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष लगातार बढ़ते रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती विद्रोही, सीरिया और इराक में विभिन्न सशस्त्र गुट तथा क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की राजनीति ने इस पूरे संकट को और अधिक जटिल बना दिया है।

साथियों, मीडिया में अनुसार 8 जून 2026 को सामने आई घटनाओं के अनुसार ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इजराइल के नेवातिम और तेल नोफ एयरबेस को लक्ष्य बनाकर मिसाइल हमले किए। ईरान का दावा है कि यह कार्रवाई लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजराइली हमलों के जवाब में की गई। दूसरी ओर इजराइली सेना ने ईरान के पश्चिमी और मध्य भागों में स्थित रडार केंद्रों, सैन्य प्रतिष्ठानों तथा अन्य रणनीतिक ठिकानों पर व्यापक हवाई हमले किए। इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संघर्ष विराम की व्याख्या दोनों पक्ष अलग-अलग तरीके से कर रहे थे। ईरान का आरोप है कि लेबनान पर इजराइली हमले सीजफायर की भावना के विरुद्ध थे, जबकि इजराइल का तर्क है कि उसकी सैन्य कार्रवाई उसकी सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप थी। इसी मतभेद ने अंततः स्थिति को फिर से युद्ध की दिशा में धकेल दिया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह संकट अब केवल ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहा। यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर मिसाइल हमले किए हैं तथा लाल सागर में इजराइली समुद्री गतिविधियों को बाधित करने की चेतावनी दी है। यदि लाल सागर और बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग प्रभावित होते हैं, तो वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।

साथियों अमेरिका इस पूरे संकट में अत्यंत चिंतित दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने सार्वजनिक रूप से दोनों पक्षों से संयम बरतने और तत्काल संघर्ष विराम की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की है। रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने इजराइली प्रधानमंत्री से बातचीत कर आगे सैन्य कार्रवाई को सीमित रखने का आग्रह किया। अमेरिकी प्रशासन की सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि यह संघर्ष पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध में बदलता है तो अमेरिका स्वयं भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें उलझ सकता है। वास्तव में यह संकट ऐसे समय में उभरा है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले से ही अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। रूस-यूक्रेन संघर्ष, व्यापारिक तनाव, मुद्रास्फीति, आपूर्ति श्रृंखला की समस्याएं और ऊर्जा बाजार की अनिश्चितता ने पहले ही विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया हुआ है।ऐसे में मध्य पूर्व में बड़े युद्ध की संभावना निवेशकों, व्यापारिक संस्थानों और सरकारों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है।

साथियों, तेल बाजार इस तनाव का सबसे पहला और सबसे संवेदनशील शिकार बनता दिखाई दे रहा है। मध्य पूर्व विश्व के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। ईरान, सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे देशों की ऊर्जा आपूर्ति वैश्विक बाजार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। संघर्ष बढ़ने की खबरों के साथ ही अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिला। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि संघर्ष लंबा खिंचता है या समुद्री मार्ग प्रभावित होते हैं तो तेल की कीमतें और अधिक बढ़ सकती हैं।तेल की कीमतों में वृद्धि का सीधा प्रभाव दुनिया के लगभग हर देश पर पड़ता है। परिवहन लागत बढ़ती है, उत्पादन महंगा होता है, महंगाई बढ़ती है और आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ सकती है। विकासशील देशों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण होती है क्योंकि वे ऊर्जाआयात पर अधिक निर्भर रहते हैं।भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देशों के लिए भी यह स्थिति चिंता का विषय है।

साथियों,भारत की दृष्टि से यह संकट कई कारणों से महत्वपूर्ण है। एक ओर भारत के ईरान, इजराइल और खाड़ी देशों के साथ मजबूत आर्थिक एवं रणनीतिक संबंध हैं, वहीं दूसरी ओर लाखों भारतीय नागरिक मध्य पूर्व में कार्यरत हैं। यदि क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ती है तो भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और व्यापारिक हित प्रभावित हो सकते हैं। इसी संदर्भ में भारत सरकार द्वारा यात्रा संबंधी सलाह जारी करना स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि संघर्ष इसी प्रकार बढ़ता रहा तो सीरिया, इराक, लेबनान और यमन जैसे देश भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसकी चपेट में आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में पूरा पश्चिम एशिया अस्थिरता के दौर में प्रवेश कर सकता है। इससे न केवल सैन्य संघर्ष बढ़ेगा बल्कि मानवीय संकट भी गहरा सकता है। लाखों लोगों के विस्थापन, शरणार्थी संकट और बुनियादी ढांचे की तबाही जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। साथियों, इतिहास गवाह है कि युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिकों को उठाना पड़ता है। मिसाइलें और बम केवल सैन्य ठिकानों को ही नहीं, बल्कि शहरों, अस्पतालों, स्कूलों और नागरिक जीवन को भी प्रभावित करते हैं। ईरान और इजराइल दोनों ही उच्च तकनीक वाले हथियारों से लैस हैं। इसलिए यदि युद्ध व्यापक रूप लेता है तो इसका मानवीय नुकसान अत्यंत गंभीर हो सकता है।संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय देशों, एशियाई शक्तियों तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे दोनों पक्षों को संवाद की मेज पर वापस लाएं। कूटनीति, मध्यस्थता और विश्वास निर्माण के उपाय ही इस संकट का स्थायी समाधान प्रदान कर सकते हैं। केवल सैन्य शक्ति के माध्यम से ऐसी जटिल समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। साथियों, विश्व राजनीति के वर्तमान परिदृश्य में यह भी स्पष्ट है कि कोई भी बड़ा क्षेत्रीय युद्ध अब केवल क्षेत्रीय नहीं रह जाता। वैश्विक वित्तीय बाजार, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य आपूर्ति, समुद्री व्यापार और अंतरराष्ट्रीय निवेश सीधे प्रभावित होते हैं।

SRLM पोर्टल बंद, भुगतान अटका, राशन नहीं मिला :महिला स्व-सहायता समूहों ने कलेक्टर से की समाधान की मांग

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। शिवपुरी जिले के सभी आठ विकासखंडों में मध्यान्ह भोजन और सांझा चूल्हा योजना का संचालन कर रही महिला स्व-सहायता समूहों की सदस्य मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचीं यहां उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया महिलाओं का कहना था कि लंबे समय से कई मुद्दों का समाधान नहीं हो पाया है जिससे समूहों को आर्थिक और प्रशासनिक दोनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

बंद पोर्टल पर पंजीयन कराने का दबाव: महिला समूहों ने ज्ञापन में बताया कि जिला पंचायत के आदेशानुसार उन्हें SRLM पोर्टल पर पंजीयन कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं जबकि संबंधित पोर्टल वर्तमान में बंद है और उस पर पंजीयन की प्रक्रिया संभव नहीं है समूहों का आरोप है कि इसके बावजूद उन पर लगातार पंजीयन कराने का दबाव बनाया जा रहा है महिलाओं ने मांग की कि जब तक पोर्टल दोबारा चालू नहीं हो जाता तब तक इस आदेश पर रोक लगाई जाए।

पंजीयन के नाम पर रुपए मांगने का आरोप: महिला समूहों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ कर्मचारी पंजीयन प्रक्रिया के नाम पर उनसे 10-10 हजार रुपए की मांग कर रहे हैं महिलाओं ने इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है उन्होंने कहा कि स्व-सहायता समूह पहले ही आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं ऐसे में इस तरह की मांगें उनकी मुश्किलें और बढ़ा रही हैं।

फरवरी से लंबित है भुगतान और मानदेय: ज्ञापन में बताया गया कि फरवरी माह से मध्यान्ह भोजन योजना की राशि का भुगतान नहीं हुआ है इसके साथ ही रसोइयों का मानदेय भी कई महीनों से लंबित है महिलाओं का कहना है कि भुगतान नहीं मिलने के कारण उन्हें उधार लेकर भोजन व्यवस्था संचालित करनी पड़ रही है इससे कई समूह आर्थिक संकट में आ गए हैं और कई महिलाएं कर्जदार हो चुकी हैं।

मध्यान्ह भोजन प्रभारी को हटाने की मांग: महिला समूहों ने ज्ञापन में मध्यान्ह भोजन प्रभारी को हटाने की मांग भी उठाई उनका कहना है कि योजना के संचालन में लगातार समस्याएं सामने आ रही हैं और जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा समय पर समाधान नहीं किया जा रहा है महिलाओं ने प्रशासन से व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की।

मार्च से जून तक खाद्यान्न नहीं मिलने का आरोप: महिला समूहों ने बताया कि मार्च से जून माह तक का खाद्यान्न उन्हें अब तक प्राप्त नहीं हुआ है जबकि संबंधित अवधि का खाद्यान्न आवंटन पहले ही जारी किया जा चुका है उन्होंने कहा कि खाद्यान्न नहीं मिलने से स्कूलों में भोजन व्यवस्था चलाना मुश्किल हो गया है कई जगहों पर समूहों को निजी स्तर पर व्यवस्था करनी पड़ रही है।

सांझा चूल्हा योजना में भी उठाए सवाल: सांझा चूल्हा योजना से जुड़ी महिलाओं ने खाद्यान्न वितरण प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए उनका आरोप है कि कुछ स्थानों पर सेल्समैन स्वयं फिंगरप्रिंट का उपयोग कर खाद्यान्न उठा लेते हैं और बाद में समूहों को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं होने की बात कह दी जाती है महिलाओं ने इसे गंभीर अनियमितता बताते हुए पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की मांग की।

अध्यक्ष और सचिव के फिंगरप्रिंट अनिवार्य करने की मांग: महिला समूहों ने मांग की कि खाद्यान्न वितरण के दौरान समूह के अध्यक्ष और सचिव के फिंगरप्रिंट को अनिवार्य किया जाए उनका कहना है कि इससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या विवाद की संभावना कम होगी और खाद्यान्न सीधे पात्र समूहों तक पहुंचेगा।

जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी: जिला अध्यक्ष रूबी पाराशर ने कलेक्टर से सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग की उन्होंने कहा कि महिला समूह लंबे समय से इन समस्याओं से जूझ रहे हैं और अब स्थिति गंभीर होती जा रही है उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भुगतान, खाद्यान्न आपूर्ति और पंजीयन से जुड़ी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो जिलेभर के महिला स्व-सहायता समूह आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।

जनशिकायतों पर कलेक्टर की सख्ती, कहा- समाधान चाहिए, सिर्फ जवाब नहीं

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिले में जनशिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण को लेकर कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों, जनशिकायतों और शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापूर्ण एवं परिणाममूलक कार्य सुनिश्चित करने पर जोर दिया बैठक में मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, प्रधानमंत्री पोर्टल, सीजी पोर्टल सहित अन्य शिकायत निवारण प्रणालियों में लंबित मामलों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि केवल औपचारिक जवाब देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी सुशासन तिहार 2026 के तहत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि यह अभियान शासन और जनता के बीच विश्वास का सेतु है। सभी आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि नागरिकों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें बैठक में नामांतरण, सीमांकन, खाता विभाजन सहित लंबित राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए। वहीं आयुष्मान भारत, महतारी वंदन योजना, सर्वाइकल कैंसर रोकथाम अभियान और एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की सभी बालिकाओं के शत-प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए शिक्षा, जनजातीय विकास, आवास, सड़क, ऊर्जा और कृषि योजनाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। उन्होंने दोहराया कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी।

नैनो यूरिया और नैनो डीएपी से बदलेगी खेती की तस्वीर, किसान सुंदर सिंह को बेहतर उत्पादन की उम्मीद

आधुनिक कृषि तकनीक अपना रहे लालपुर के किसान, बोले- समय पर मिल रही खाद, नई तकनीक से बढ़ेगा लाभ

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। खेती को अधिक लाभकारी और आधुनिक बनाने की दिशा में जिले के किसान अब नई तकनीकों को तेजी से अपना रहे हैं इसी कड़ी में जिला एमसीबी के ग्राम लालपुर निवासी किसान सुंदर सिंह ने इस खरीफ सीजन में पहली बार नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का उपयोग करने का निर्णय लिया है उन्हें विश्वास है कि आधुनिक उर्वरकों के प्रयोग से उनकी फसल की बढ़वार बेहतर होगी और उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी सुंदर सिंह बताते हैं कि अब तक वे पारंपरिक उर्वरकों का उपयोग करते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से नैनो उर्वरकों के सकारात्मक परिणामों की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने भी इसे अपनाने का निर्णय लिया उनका कहना है कि गांव और आसपास के कई किसानों ने पिछले वर्ष नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का उपयोग किया था, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए। किसानों ने फसलों की बेहतर वृद्धि, पौधों के अच्छे स्वास्थ्य और उत्पादन में वृद्धि का अनुभव किया उन्होंने कहा कि नैनो उर्वरकों की सबसे बड़ी विशेषता इसकी उपयोगिता और सुविधा है पारंपरिक उर्वरकों की तुलना में कम मात्रा में उपयोग होने के बावजूद यह प्रभावी परिणाम देता है साथ ही इसे आसानी से परिवहन किया जा सकता है जिससे किसानों का समय श्रम और लागत तीनों की बचत होती है सुंदर सिंह ने बताया कि सहकारी समिति से किसानों को खाद समय पर उपलब्ध हो रही है, जिससे खेती की तैयारियों में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही। आवश्यकतानुसार उर्वरकों की उपलब्धता से किसानों में संतोष है और वे पूरे उत्साह के साथ खरीफ सीजन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उन्होंने शासन और कृषि विभाग की पहल की सराहना करते हुए कहा कि किसानों को लगातार आधुनिक कृषि तकनीकों तथा संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है इससे किसानों में नई तकनीकों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और वे नवाचारों को अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं सुंदर सिंह का मानना है कि बदलते समय के साथ यदि किसान आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाएं तो खेती अधिक उत्पादक और लाभकारी बन सकती है उन्हें उम्मीद है कि नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग से इस वर्ष उनकी फसल बेहतर होगी और उनकी सफलता अन्य किसानों को भी नई तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित करेगी नैनो उर्वरकों के बढ़ते उपयोग के साथ जिले में आधुनिक कृषि की नई तस्वीर उभर रही है जहां किसान नवाचार, सुविधा और बेहतर उत्पादन की दिशा में आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ा रहे हैं।

सिद्धेश्वर मेले में अवैध वसूली, बिजली चोरी के आरोप :दुकानदारों ने सुविधाओं की कमी और झूलों के संचालन पर उठाए सवाल

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। प्राचीन सिद्धेश्वर मेले में व्यवस्थाओं को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है दूर-दराज के जिलों और अन्य राज्यों से आए दुकानदारों ने मेला ठेकेदार पर मूलभूत सुविधाएं न देने और अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाए हैं दुकानदारों का आरोप है कि उनसे हजारों रुपए वसूलने के बावजूद पीने के पानी नहाने और शौच जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं मुरैना से आए कॉस्मेटिक दुकानदार मोनू और बिहार से चश्मे की दुकान चला रहे दीपक कुमार ने बताया कि प्रत्येक दुकान से लगभग 25 हजार रुपए तक लिए गए हैं दुकानदारों ने यह भी आरोप लगाया कि रोशनी के लिए प्रति बल्ब 100 रुपए प्रतिदिन वसूले जा रहे हैं इस प्रकार, चार बल्ब लगाने पर उन्हें प्रतिदिन 400 रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ रहा है सुविधाओं के अभाव के कारण कुछ दुकानदारों को किराए के कमरे लेकर रहना पड़ रहा है वहीं आर्थिक रूप से कमजोर दुकानदार मेले परिसर में ही रहने को मजबूर हैं मेला परिसर के बाहर पानीपुरी सोडा और अन्य खाद्य सामग्री के हाथ ठेले लगाने वाले व्यापारियों ने भी अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं अशोक और रासिफ जैसे कई ठेला संचालकों ने बताया कि वे सालभर उसी स्थान पर व्यापार करते हैं लेकिन मेले के दौरान उनसे प्रतिदिन 100 रुपए वसूले जा रहे हैं मेले में संचालित झूलों को लेकर भी गंभीर आरोप सामने आए हैं आरोप है कि झूलों को बिजली के खंभों से सीधे तार डालकर चलाया जा रहा है। मंगलवार तक मेला ठेकेदार द्वारा अस्थाई बिजली कनेक्शन नहीं लिया गया था, जिससे बिजली चोरी कर झूलों का संचालन होने की बात कही जा रही है इस मामले में मेला ठेकेदार आकाश शिवहरे और भागचंद शिवहरे से संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया उल्लेखनीय है कि ठेका भुगतान विवाद को लेकर दो दिन पहले एसडीएम द्वारा मेले में तालाबंदी की कार्रवाई भी की गई थी, जिससे आमजन और व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था बिजली विभाग के एई बघेल ने बताया कि मेला ठेकेदार द्वारा दो दिन पहले अस्थाई बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन दिया गया था। तब तक जनरेटर से व्यवस्था संचालित करने की बात कही गई थी। मंगलवार को मेले में अस्थाई मीटर लगाया जाएगा और अवैध बिजली उपयोग की जांच भी कराई जाएगी।

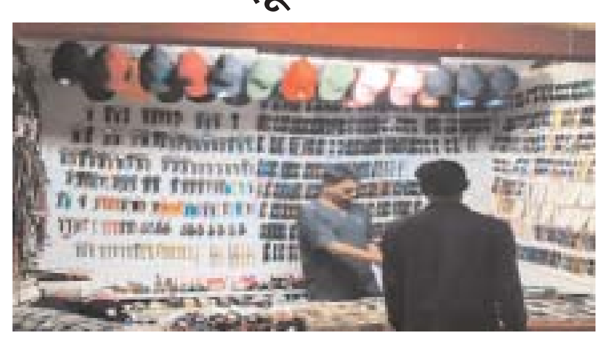

हॉकी एशिया कप विजेता अंश का स्वागत :जापान को 4-1 से हराकर चैंपियन बनी टीम इंडिया; तिरंगा देकर हुआ सम्मान

मीडिया ऑडीटर, नर्मदापुरम (निप्र)। जापान में अंडर-18 हॉकी एशिया कप-2026 जीतकर लौटी भारतीय टीम के खिलाड़ी अंश बहुत्रा का सोमवार को नर्मदापुरम में भव्य स्वागत किया गया। सुबह 10 बजे भोपाल चौराहे पर शहर के लोगों ने अंश को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा सौंपा और फूल-मालाएं पहनाकर जीत की बधाई दी इस ऐतिहासिक खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया ने डिफेंडिंग चैंपियन जापान को 4-1 से हराकर एशिया कप पर कब्जा जमाया है जापान में 6 जून को अंडर-18 हॉकी पुरुष एशिया कप का फाइनल मुकाबला खेला गया था खिताबी भिड़ंत में भारत के सामने डिफेंडिंग चैंपियन जापान की कड़ी चुनौती थी टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही जापानी टीम ने पूल राउंड में भारत को भी हराया था लेकिन फाइनल में भारतीय टीम ने 4-1 से शानदार जीत दर्ज कर हार का हिसाब बराबर कर लिया। इससे पहले सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से करारी शिकस्त देकर फाइनल का टिकट कटाया था नर्मदापुरम के तीन खिलाड़ियों ने बढ़ाया जिले का मान खिताबी जीत हासिल करने वाली इस भारतीय टीम में नर्मदापुरम जिले के तीन होनहार खिलाड़ी शामिल रहे। अंश बहुत्रा, गाजी खान और महक परिहार ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से पूरे देश के साथ-साथ जिले का भी मान बढ़ाया है। जीत के बाद नर्मदापुरम पहुंचने पर अंश का मिठाई खिलाकर आत्मीय सम्मान किया गया इस अवसर पर हॉकी कोच जयसिंह भदौरिया, पवन कुमार, हॉकी संघ के पूर्व अध्यक्ष रोहित फौजदार महेंद्र पचलानिया मेहरबान सिंह परिहार और मनीष परदेशी विशेष रूप से मौजूद रहे टर्फ स्टेडियम से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाई पहचान जिले के लिए यह बेहद गौरव का विषय है कि नर्मदापुरम लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ी देश को दे रहा है इससे पहले ओलंपियन और डीएसपी विवेक सागर ने भी जिले का नाम रोशन किया था हॉकी संघ के संरक्षक रोहित फौजदार ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा ये सभी होनहार खिलाड़ी स्थानीय टर्फ स्टेडियम में खेलकर ही इस मुकाम तक पहुंचे हैं और आगे बढ़े हैं इन तीनों एशियन विनर खिलाड़ियों की सफलता के पीछे कोच जय सिंह भदौरिया पवन वर्मा, वंदना उइके और उपेंद्र शर्मा का कड़ा प्रशिक्षण रहा है।

बिना सूचना के लंबे समय से लापता शिक्षक को अंतिम चेतावनी : 15 दिन में जवाब न देने पर सेवा होगी समाप्त

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर ने अनाधिकृत रूप से ड्यूटी से गायब सहायक शिक्षक को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी किया है लगातार अनुपस्थित रहने और पहले भेजे गए नोटिसों का जवाब न देने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है शिक्षक को 15 दिनों के भीतर उपस्थित होकर जवाब देने का अंतिम अवसर दिया गया है ऐसा न करने पर सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी।

सितंबर 2024 से लगातार गायब हैं शिक्षक: यह मामला प्राथमिक शाला रामानुजनगर में पदस्थ सहायक शिक्षक नीतेश कुमार पाण्डे का है। वे 20 सितंबर 2024 से लगातार अपने कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित चल रहे हैं। इस दौरान विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (BEO) कार्यालय द्वारा उनके निवास पते पर पंजीकृत डाक के माध्यम से कई कारण बताओ पत्र भेजे गए लेकिन शिक्षक की ओर से कोई जवाब नहीं आया।

सेवाकाल और नियमों का उल्लंघन: जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पत्र के अनुसार शिक्षक नीतेश कुमार पाण्डे की नियुक्ति के बाद से गणना की जाए तो अभी तक उनकी परिवीक्षा अवधि (Probation Period) भी पूरी नहीं हुई है ऐसी स्थिति में बिना सूचना लंबे समय तक ड्यूटी से गायब रहना सेवा में बने रहने के लिए वैधानिक नहीं है निर्धारित समय में जवाब न देना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन माना गया है 15 दिनों का अंतिम अवसर प्रशासन ने शिक्षक को 15 दिन के भीतर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय मनेन्द्रगढ़ में उपस्थित होकर अपना समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है यदि तय समय में जवाब नहीं मिलता है तो यह मान लिया जाएगा कि वे शासकीय सेवा के इच्छुक नहीं हैं ऐसी स्थिति में शासन के नियमों के तहत उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे इस संबंध में संकुल प्राचार्य और संकुल शैक्षिक समन्वयक पसौरी को भी निर्देशित किया गया है कि यदि शिक्षक कार्यभार ग्रहण करने आते हैं तो जिला कार्यालय की अनुमति के बाद ही उन्हें जॉइनिंग दी जाए

नगरपालिका के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन :विकास कार्यों में भेदभाव दूषित पेयजल आपूर्ति का आरोप, मौके पर पहुंचीं डिप्टी कलेक्टर

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। मनेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में कांग्रेस नेताओं और पार्षदों ने नगरपालिका कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया यह प्रदर्शन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ मिश्रा और सांसद प्रतिनिधि गोपाल गुप्ता के संयुक्त नेतृत्व में आयोजित किया गया प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि नगरपालिका प्रशासन विपक्षी वार्डों के विकास कार्यों की लगातार उपेक्षा कर रहा है। कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि नागरिकों से राशि जमा कराने के बाद भी कांग्रेसी वार्डों में नल कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि भाजपा पार्षदों के वार्डों में विकास कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं भाजपा पार्षदों के परिजनों के हस्तक्षेप पर जताई आपत्ति कांग्रेस नेताओं ने नगरपालिका के कार्यों में भाजपा की महिला पार्षदों के पतियों के अनावश्यक और अवैध हस्तक्षेप का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है।

दूषित पेयजल आपूर्ति को लेकर नाराजगी: कांग्रेस पार्षदों ने शहर के कई वार्डों में दूषित पेयजल आपूर्ति पर भी नाराजगी जताई उन्होंने नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने और व्यवस्था में तत्काल सुधार की मांग की।

छह पार्षद रहे प्रदर्शन में शामिल: नगरपालिका कार्यालय के घेराव और प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कुल नौ पार्षदों में से छह पार्षद मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हुएडिप्टी कलेक्टर ने की चर्चा प्रदर्शन के दौरान माहौल गरमाता देख प्रशासन की ओर से डिप्टी कलेक्टर इंदिरा मिश्रा मौके पर पहुंचीं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं और पार्षदों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं।

आश्वासन के बाद समाप्त हुआ प्रदर्शन: डिप्टी कलेक्टर ने समस्याओं के निराकरण और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया इसके बाद कांग्रेस नेताओं और पार्षदों ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया।

समाधान नहीं हुआ तो होगा बड़ा आंदोलन: कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो भविष्य में और बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

मनेंद्रगढ़ में विदेशी मदिरा दुकान संचालन हेतु किराये के भवन के लिए लघु निविदा आमंत्रित

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। वित्तीय वर्ष 2026-27 में विदेशी मदिरा दुकान के सुचारु संचालन के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीएसएमसीएल) द्वारा मनेंद्रगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में उपयुक्त किराये के भवन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु लघु निविदा आमंत्रित की गई है इस संबंध में जिला स्तर पर निविदा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है जिला आबकारी अधिकारी सह जिला प्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर द्वारा जारी सूचना के अनुसार विदेशी मदिरा दुकान के संचालन के लिए ऐसे भवनों का चयन किया जाएगा, जो निर्धारित मानकों एवं आवश्यक सुविधाओं के अनुरूप हों। चयनित भवन अधिपत्य तिथि से 31 मार्च 2027 तक किराये पर लिया जाएगा इच्छुक भवन स्वामियों एवं निविदाकारों से तकनीकी बिड एवं प्राइस बिड पृथक-पृथक बंद लिफाफे में आमंत्रित की गई हैं। निविदा प्रपत्र 22 जून 2026 को दोपहर 2 बजे तक जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में जमा किए जा सकेंगे। प्राप्त निविदाओं को उसी दिन शाम 4 बजे गठित समिति द्वारा निविदाकारों की उपस्थिति में खोला जाएगा। इसके बाद तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्तावों का परीक्षण नियमानुसार किया जाएगा तथा पात्र आवेदनों पर आगे की प्रक्रिया संपादित की जाएगी।

बहन की शादी से पहले भाई की हादसे में मौत बारातियों के नाश्ते की तैयारी के दौरान भैंस से टकराया खुशियों का माहौल मातम में बदला

मीडिया ऑडीटर,छतरपुर (निप्र)। छतरपुर जिले के लवकुशनगर थाना क्षेत्र के बागमऊ गांव में शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गई, जब दुल्हन के 14 वर्षीय छोटे भाई की सड़क हादसे में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, चेतराम अहिरवार की बेटी वंदना अहिरवार की शादी थी। सोमवार रात बारात गांव पहुंची थी और शादी की रस्में चल रही थीं। मंगलवार सुबह फेरों की तैयारी की जा रही थी। इसी दौरान बारातियों के लिए चाय-नाश्ते की व्यवस्था के बीच डिस्पोजल प्लेट और गिलास कम पड़ गए। परिवार ने दुल्हन के छोटे भाई भीम अहिरवार को बाइक से गांव की दुकान पर डिस्पोजल सामान लेने भेजा। सामान लेकर लौटते समय खेतों के पास उसकी बाइक अचानक सामने आई एक भैंस से टकरा गई। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

इलाज में लापरवाही का आरोप: परिजन घायल भीम को तुरंत लवकुशनगर अस्पताल लेकर पहुंचे। उनका आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं थे और करीब एक घंटे तक केवल नर्सों ने प्राथमिक उपचार किया।

नगर पालिका द्वारा वर्षा से पहले की जा रही नाले-नालियों की सफाई

मीडिया ऑडीटर,सीहोर (निप्र)। । कलेक्टर बालागुरू के. के निर्देशानुसार सीहोर नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा वर्षा ऋतु से पहले नगर के नालों एवं नालियों की साफ-सफाई का कार्य किया जा रहा है। नगर पालिका सीएमओ सुधीर कुमार सिंह ने बताया नगर की सभी चौक एवं ओवरफ्लो नालियों की सफाई की जा रही है, ताकि वर्षाकाल के दौरान नागरिकों को कोई परेशानी न हो। इसके साथ ही टाउनहाल, इंग्लिशपुरा, दूल्हाबादशाह, दीवानबाग और कस्बे से होकर निकलने वाले नाले की सफाई का कार्य भी प्रारंभ किया जा रहा है, ताकि वर्षा के दौरान जल भराव की स्थिति न बने।

बिजली कंपनी द्वारा शिविर लगाकर किया जा रहा बिजली संबंधी समस्याओं का निराकरण

मीडिया ऑडीटर, सीहोर (निप्र)।, विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। महाप्रबंधक पूनम तुमराम ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के साथ सीधा संवाद कर उन्हें त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना और उनकी शिकायतों का त्वरित निराकरण करना है। विद्युत वितरण केन्द्रवार बनाए गये कलस्टरों पर शिविर लगाए जा रहे हैं। शिविरों में बिजली उपभोक्ताओं की बिल, मीटर, सर्विस केबल, कनेक्शन एवं तकनीकी सेवाओं संबंधी शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत 08 जून को सीहोर संभाग अंतर्गत ग्राम जमोनिया तालाब, शिकारपुर, मुस्करा, पडली, सीहोर शहर के वार्ड 19, वार्ड 10 एवं आष्टा संभाग अंतर्गत ग्राम शेखुखेड़ा, बेदाखेड़ी, आष्टा शहर के वार्ड नं. 08, ग्राम किल्लोद में शिविर लगाकर बिजली संबंधी समस्याओं का निराकरण किया गया।

रतलाम में पति-पत्नी ने खाया जहर, मौत

पिता ने सुबह कमरे में जाकर देखा तो बेसुध मिले बेटा-बहू, डॉक्टर से बोला- सल्फास खाया

मीडिया ऑडीटर,रतलाम (निप्र)। रतलाम के ताल में पति-पत्नी ने कीटनाशक खाकर अपनी जान दे दी। सोमवार सुबह जब वह सोकर नहीं उठे तो युवक के पिता ने जाकर दरवाजा खोला तो बेटा-बहू दोनों बेसुध मिले। तुरंत दोनों को ताल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जहां महिला को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जबकि बेटे की हालात गंभीर होने पर रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया। यहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

कमरे में बेहोश मिले बेटा-बहू: मृतक का नाम संजू उर्फ संजय (31) पिता सत्यनारायण प्रजापति व पत्नी का नाम मंजू (30) है। ताल पुलिस के अनुसार सुबह जब पति-पत्नी नहीं उठे तो घर में अलग कमरे में सो रहे पिता ने जाकर उठाने की कोशिश की। लेकिन बेटे-बहू दोनों बेसुध अवस्था में थे। तुरंत दोनों को ताल के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जहां महिला को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। युवक की हालात गंभीर होने रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया। परिजन सोमवार सुबह 8 बजे उसे लेकर रतलाम पहुंचे। लेकिन कुछ ही देर में संजू की भी मौत गई।

मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला: सुबह घटना की जानकारी मिलने पर ताल थाना प्रभारी स्वराज डाबी बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का मौका मुआयना किया। लेकिन घर में किसी प्रकार से कोई सुसाइड लेटर व अन्य सामग्री नहीं मिली है।

पिता से बोला- दवाई खा ली: मृतक के बड़े भाई मुकेश प्रजापति ने बताया कि मेरा घर भी पास में है। सुबह छोटा भाई संजू 4 बजे उठकर घर के बाहर उल्टी करने आया था। तब पास के कमरे में पिता की नींद खुल गई थी। पिता ने उससे पूछा तो उसने कहा कि दवाई खा ली है। फिर कमरे में जाकर देखा तो उसकी पत्नी भी मृत अवस्था में थी। पिता मुझे बुलाने आए, इसके बाद दोनों को ताल के स्वास्थ्य केंद्र केंद्र लेकर गए। जहां बहू को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। भाई की हालात गंभीर होने पर रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया। यहां पर कुछ देर में इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। दोपहर में संजू का पीएम हुआ। भाई ने यह भी आरोप लगाया कि सुबह ताल से रतलाम लाने के लिए स्वास्थ्य केंद्र से एंबुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई। प्राइवेट गाड़ी कर रतलाम लाना पड़ा। मायके पक्ष के आने के बाद होगा पत्नी का पीएम पति का पीएम रतलाम मेडिकल कॉलेज में हो गया लेकिन पत्नी का पीएम नहीं हो पाया। पत्नी के मायके पक्ष हरदा जिले के टिमरनी में होने पर परिजन दोपहर तक ताल नहीं पहुंच पाए। देर रात तक परिजन पहुंचेंगे। इस कारण अब मंगलवार सुबह पीएम होगा। उसी के बाद पति के शव को भी रतलाम से ताल ले जाया जाएगा।

संजू मिस्त्री का करता था का: संजू मिस्त्री का काम करता था। 5 जून को पत्नी को उसके मायके से लेकर आया था। भाई मुकेश के अनुसार छोटे भाई के ससुराल में किसी का निधन होने पर वह गया।

बहू दो से ढाई माह से गर्मी की छुट्?टी के कारण मायके में थी। भाई लौटते वक्त उसकी पत्नी और बच्चों को लेकर ताल आया था।

संजू के दो बच्चे है। जिनमें 8 साल का एक लड़का व 6 साल की बेटी है। घर में पिता साथ रहते है। जबकि बड़ा भाई मुकेश अपने परिवार के साथ पास में रहता है। मृतक की मां का कोरोना काल में निधन हो चुका है।

रात में हुआ था झगड़ा: पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि रविवार रात पति-पत्नी में विवाद हुआ था। कमरे में जोर-जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। हालांकि विवाद का कारण सामने नहीं आया है।

मलेरिया के प्रति जनजागरूकता लाने प्रचार रथ को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना

मीडिया ऑडीटर,रायसेन (निप्र)। प्रति वर्ष भांति इस वर्ष भी मलेरिया निरोधक माह 01 जून से 30 जून तक मनाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य वर्षा ऋतु के दौरान मच्छरों की बढ़ती संख्या से होने वाली मलेरिया, डेंगू एवं चिकुनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियों के प्रति जनसामान्य को जागरूक करना तथा इन रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण सुनिश्चित करना है। जिसके अंतर्गत सोमवार को जिला पंचायत सीईओ कमल सोलंकी द्वारा जनजागरूकता रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। मलेरिया जनजागरूकता रथ द्वारा मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में और दूरस्थ व दुर्गम पहुंच वाले ग्रामों में मलेरिया के नियंत्रण तथा बचाव करने के लिए प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इस दौरान जिला टीकाकरण अधिकारी और जिला मलेरिया अधिकारी भी उपस्थित रहे। मलेरिया निरोधक माह जून के कार्यक्रम अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों, पंचायत स्तर और ग्रामीण स्तर पर जनसामान्य को जागरूक करने के लिए माईकिंग, सघन लार्वा सर्वे, बुखार के रोगियों की जांच, नारे लेखन एवं एडवोकेसी बैठक आयोजित की जा रही हैं। जिसमें लोगों को मच्छरों से बचने के उपाय के बारे में बताया जा रहा है। मलेरिया, डेंगू, चिकिनगुनिया के नियंत्रण हेतु लार्वा विनष्टिकरण, जांच एवं उपचार के बारे में भी समझाईश दी जा रही है।

सागर में पकड़ाया 3 फीट लंबा रसेल वाइपर

सोफे के नीचे छिपा बैठा था, पकड़ते ही मारी फुफकार

मीडिया ऑडीटर,सागर (निप्र)। सागर की गुरुधाम कॉलोनी में सोमवार को एक मकान में जहरीला सांप निकलने से हड़कंप मच गया। मकान मालिक जब घर पहुंचे तो उन्होंने बाल्टी के पास एक सांप को बैठे देखा। सांप को देखते ही परिवार के लोग घबरा गए और तुरंत घर से बाहर निकल आए। इसके बाद स्नेक कैचर अकील बाबा को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे और सांप का रेस्क्यू शुरू किया।

बाल्टी के पास बैठा मिला सांप: जानकारी के अनुसार मकान मालिक घर पहुंचे तो उनकी नजर बाल्टी के पास बैठे सांप पर पड़ी। सांप को देखते ही उन्होंने कोई जोखिम नहीं लिया और तुरंत परिवार के अन्य सदस्यों को बाहर निकाल लिया। परिवार ने समझदारी दिखाते हुए सांप को पकड़ने की कोशिश नहीं की और सीधे स्नेक कैचर को सूचना दी। सूचना मिलते ही शुरू हुआ रेस्क्यू सूचना मिलने के बाद स्नेक कैचर अकील बाबा मौके पर पहुंचे। उन्होंने घर के अंदर जाकर सांप की तलाश शुरू की। कुछ देर खोजबीन के बाद सांप सोफे के पीछे छिपा हुआ मिला। सांप को बाहर निकालने के लिए पहले सोफा हटाया गया, जिसके बाद उसे पकड़ने की कोशिश शुरू की गई।

पकड़ते समय सांप ने मारी जोरदार फुफकार: रेस्क्यू के दौरान जैसे ही स्नेक कैचर ने सांप को नियंत्रित करने का प्रयास किया, उसने तेज फुफकार मारना शुरू कर दिया।

हालांकि अनुभव और सावधानी के चलते स्नेक कैचर ने स्थिति को संभाल लिया। काफी सतर्कता के साथ सांप को सुरक्षित पकड़ा गया और उसे लोगों से दूर कर लिया गया। कोबरा नहीं, निकला रसेल वाइपर स्नेक कैचर अकील बाबा ने बताया कि उन्हें फोन पर सूचना दी गई थी कि घर में कोबरा प्रजाति का सांप दिखाई दिया है। लेकिन मौके पर पहुंचकर देखा गया तो वह रसेल वाइपर प्रजाति का सांप निकला। उन्होंने बताया कि सांप की लंबाई करीब 3 फीट थी और यह बेहद जहरीली प्रजाति का सांप है। एशिया के सबसे खतरनाक सांपों में शामिल अकील बाबा के अनुसार रसेल वाइपर एशिया के सबसे खतरनाक और जहरीले सांपों में गिना जाता है। इसके काटने पर व्यक्ति की जान को गंभीर खतरा हो सकता है यदि

पर्यावरण बचाओ अभियान के अंतर्गत किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

मीडिया ऑडीटर,सीहोर (निप्र)। कृषि विभाग द्वारा 'पर्यावरण बचाओ अभियान' के अंतर्गत ग्राम राला में किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा किसानों को मृदा परीक्षण के महत्व के संबंध में जानकारी दी गई। कृषकों को संतुलित उर्वरक उपयोग के महत्व से अवगत कराते हुए नत्रजन, फास्फोरस, पोटाश एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों के वैज्ञानिक एवं अनुशंसित मात्रा में प्रयोग करने की सलाह दी गई। इसके अतिरिक्त समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के अंतर्गत रासायनिक उर्वरकों के साथ-साथ जैविक खाद, वर्मी कम्पोस्ट, गोबर खाद, हरी खाद एवं जैव उर्वरकों के समन्वित उपयोग पर विशेष बल दिया गया। किसानों को बताया गया कि इससे मृदा की उर्वराशक्ति दीर्घकाल तक बनी रहती है तथा पर्यावरण संरक्षण में भी सहायता मिलती है।

रायसेन में हार्वेस्टर और बाइक की भिड़ंत रिश्तेदार के घर से लौट रही 56 वर्षीय महिला की मौत

मीडिया ऑडीटर,रायसेन (निप्र)। रायसेन जिले के सिलवानी थाना क्षेत्र में सोमवार शाम एक भीषण सड़क हादसा हो गया। ग्राम बेरुआ के पास एक हार्वेस्टर और बाइक की आमने-सामने की टक्कर में 56 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, बाइक चला रहा उनका बेटा घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार, सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुरा निवासी 56 वर्षीय शाहेजहां अपने बेटे के साथ जैथारी क्षेत्र में एक रिश्तेदार के घर गई थीं। सोमवार शाम दोनों वहां से चंदनपिपरिया की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान ग्राम बेरुआ के पास उनकी बाइक सामने से आ रहे हार्वेस्टर से टकरा गई।

हार्वेस्टर के नीचे दबी बाइक, बेटे ने नहीं पहना था हेलमेट: दोनों वाहनों के बीच टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सीधे हार्वेस्टर के नीचे जा घुसी और दब गई। इस दर्दनाक हादसे में शाहेजहां ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और उनका बेटा घायल हो गया। प्राथमिक जानकारी में सामने आया है कि बाइक चला रहे बेटे ने घटना के वक्त हेलमेट नहीं पहना था।

मंगलवार सुबह होगा मृतका का पोस्टमार्ट हादसे की सूचना मिलते ही जैथारी चौकी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को घटनास्थल से उठवाकर सिलवानी सिविल अस्पताल भिजवा दिया है।

खंडवा-बुरहानपुर हाईवे पर बस से भिड़ी आयशर गाड़ी लहसुन से भरा ट्रक बेकाबू हुआ बस के कांच फूटे, यात्री भी घायल

मीडिया ऑडीटर, खंडवा (निप्र)। खंडवा-बुरहानपुर नेशनल हाईवे पर झिरी गांव के पास सोमवार को एक ट्रक ने यात्री बस को टक्कर मार दी। हादसे में बस के आगे के कांच टूट गए, एक हिस्से से वह पिचक गई। वहीं लहसुन के कट्टों से खचाखच भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटी खा गया। इस दौरान मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। बस में सवार यात्रियों के बीच चीख-पुकार मच गई। इस दौरान लोग अपनी जान बचाने के लिए जल्दबाजी में बस से बाहर निकलने लगे। इधर, दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंच गए। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई। मिली जानकारी के अनुसार आर्या ट्रेवल्स की यात्री बस खंडवा से बुरहानपुर की ओर जा रही थी, तभी हाईवे पर सामने से आ रहे एक ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना में कई यात्रियों को चोटें आई हैं, हालांकि घायलों की आधिकारिक संख्या की पुष्टि नहीं हो सकी थी।

हादसे के बाद मची अफरा-तफरी: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर के तुरंत बाद बस में बैठे यात्रियों में दहशत फैल गई। कई यात्री सीटों से उछल गए, जबकि कुछ को मामूली और कुछ को गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए राहत कार्य शुरू किया और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की। बाद में पुलिस और एंबुलेंस टीम ने घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया।

चालक एक-दूसरे पर लगा रहे आरोप: हादसे के बाद बस चालक और ट्रक चालक दोनों पक्ष दुर्घटना के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एक पक्ष का दावा है कि सामने वाले ट्रक वाहन ने लापरवाही से वाहन चलाया, जबकि दूसरा पक्ष भी यही आरोप लगा रहा है। ऐसे में दुर्घटना के वास्तविक कारणों को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस ने शुरू की जांच घटना की सूचना मिलते ही संबंधित थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनास्थल का निरीक्षण किया। बाद में मामले को बुरहानपुर पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, वाहन चालकों से पूछताछ और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर हादसे के कारणों का पता लगाया जाएगा।

प्रदेश के प्रत्येक विद्यार्थी की होगी अपनी विशिष्ट अपार आईडी

मीडिया ऑडीटर, रायसेन (निप्र)। । प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का शैक्षणिक रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित और एक ही जगह पर उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में अपार आईडी निर्माण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी की अपार आईडी बनाने का कार्य किया जाएगा। साथ ही प्रदेश की समस्त स्कूलों में प्रत्येक शनिवार को मेगा अपार दिवस का आयोजन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा के आंकडों के अनुसार प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 39 लाख 38 हजार स्कूली विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाई जाएगी। अब तक 93 लाख 97 हज़ार विद्यार्थियों की अपार आईडी का निर्माण हो चुका है। शेष 44 लाख 47 हज़ार विद्यार्थियों की अपार आईडी का निर्माण आगामी 30 जून तक पूरा जाएगा। प्रदेश की सभी स्कूलों में ष्मेगा अपार दिवसष् का 30 जून तक आयोजन किया जाएगा। यह प्रत्येक शनिवार को होगा। इसी कडी में आज 6 जून को स्कूलों में पहले अपार दिवस का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में अभिभावकों के साथ स्कूल पहुंचे विद्यार्थियों ने अपना अपार पंजीयन कराया। अपार आईडी किसी भी विद्यार्थी के लिए जीवन भर की डिजीटल शैक्षणिक पहचान होती है। इसमें विद्यार्थी के सभी शैक्षणिक रिकॉर्ड्स एक जगह सुरक्षित रहते हैं। यह एक डिजीटल और पेपरलेस रिकार्ड सिस्टम है। अपार आईडी, छात्रवृति, प्रवेश एवं सरकारी योजनाओं में सहायक होने के साथ ही कहीं भी कभी भी उपयोगी होगी है। विद्यार्थियों की अपार आईडी निर्मित करवाने के लिए आयुक्त लोक शिक्षण और संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र ने मई माह में संयुक्त हस्ताक्षर से सभी जिला कलेक्टर्स को पत्र प्रेषित किया था। जिसके अनुक्रम में इन शिविरों में अपार आईडी से वंचित विद्यार्थियों के अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण कराई जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जिले एवं विकासखंड-वार 'अपार आईडी विहीन विद्यार्थियों' की विद्यालयवार सूची तैयार कर मैदानी अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई है। जिन विद्यार्थियों के पास आधार नहीं है, उनके लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जिला आधार नामांकन केंद्र, बैंक, डाकघर के माध्यम से आधार नामांकन का कार्य भी प्राथमिकता से करवाया जा रहा है। जिससे आधार के अभाव में इस अपार आईडी के निर्माण में कोई बाधा ना आए। विद्यार्थियों के आधार नामांकन में अथवा छ्ढ्ढस्ङ्ख+ पोर्टल पर नाम की भिन्नता, आधार सीडिंग त्रुटि अथवा पालक/ अभिभावक की सहमति संग्रहण में विलंब जैसी बाधाओं को पहचान कर तत्काल दूर करने के निर्देश भी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान किए गए हैं। अपार आईडी निर्माण के लिए स्कूल के प्रधानाध्यापक होंगे उत्तरदायी विद्यार्थियों को अपार आईडी पंजीयन में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसके लिए भारत सरकार द्वारा अपार पोर्टल पर विद्यार्थी के पंजीयन के अधिकार संबंधित शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्य एवं प्रधानाध्यापकों को प्रदान किए गए हैं।

वैभव सूर्यवंशी का अनूठा डाइट प्लानः

स्वाद से समझौता नहीं प्रदर्शन में कोई कमी नहीं

नई दिल्ली एजेंसी। आधुनिक क्रिकेट में अब खिलाड़ियों का प्रदर्शन केवल उनके कौशल तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि फिटनेस भी टीम में चयन का एक महत्वपूर्ण पैमाना बन चुकी है। खिलाड़ी न केवल घंटों नेट पर पसीना बहाते हैं, बल्कि जिम में कठोर वर्कआउट करते हुए अनुशासित डाइट प्लान का भी पालन करते हैं पर उभरते क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का अंदाज इससे अलग है। महज 15 साल की उम्र में अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचने वाले वैभव खाने के बहुत शौकीन हैं और किसी प्रकार का परहेज नहीं रकते। उनके इस शौक के कारण कई बार उनकी फिटनेस पर सवाल भी उठे, लेकिन मैदान पर उनके धमाकेदार खेल पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। ऐसे में क्रिकेट प्रेमी यह जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर 15 साल के इस उभरते हुए बल्लेबाज को किस तरह का खाना पसंद है और उनका डाइट प्लान क्या है।

वैभव अपने एक बार कहा था कि उन्हें घर का बना खाना बेहद पसंद है। खासतौर पर नॉनवेज फूड में उन्हें मटन खाने का बहुत शौक है, जिसे वह बेहद चाव से खाते हैं। इसके अलावा, चिकन और हाई प्रोटीन के लिए मछली भी उनकी डाइट का हिस्सा हैं। सिर्फ मांसाहारी भोजन ही नहीं, वैभव मिठाई के भी बहुत बड़े शौकीन हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता है, वह स्वादिष्ट राजभोग का स्वाद लेते हैं। इसके साथ ही आइसक्रीम भी उनकी पसंदीदा चीजों में से एक है। फिलहाल, वैभव खाने-पीने में कोई खास परहेज नहीं करते और जो उन्हें पसंद आता है, उसे खाते हैं। उनका यह बेपरवाह अंदाज आज के युवा खिलाड़ियों के सख्त डाइट रूटीन से काफी अलग है।

यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि आईपीएल 2026 के दौरान जब वैभव से उनकी फिटनेस के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि वह धीरे-धीरे अपने डाइट प्लान में बदलाव करेंगे। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए उन्हें अपनी फिटनेस को और बेहतर बनाना होगा। हालांकि, वैभव दिखने में भले ही थोड़े भारी लगते हों, लेकिन मैदान पर जब उनका बल्ला बोलता है, तो पता चलता है कि वह पूरी तरफ से फिट हैं।

यही कारण है कि कई क्रिकेट विशेषज्ञों ने उन्हें अपने खान-पान में तत्काल कोई बड़ा बदलाव न करने की सलाह भी दी है, ताकि उनके स्वाभाविक खेल पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। वैभव अपने खेल और खाने के बीच एक ऐसा संतुलन बनाए हुए हैं, जो उन्हें एक विशिष्ट पहचान देता है और भविष्य में जब वह अपनी फिटनेस पर और काम करेंगे, तो निश्चित रूप से और भी खतरनाक बल्लेबाज बनकर उभरेंगे।

डेब्यू टेस्ट में छाए मानव सुथार

भारतीय क्रिकेट को मिला नया स्पिन सितारा

चंडीगढ़ एजेंसी। भारतीय क्रिकेट को युवा स्पिनर मानव सुथार के रुप में एक नया स्पिन सितारा मिल गया है। सुथार ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट मैच में सनसनीखेज प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित किया है। मुल्लांपुर स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस एकमात्र टेस्ट मुकाबले में सुथार ने अपनी करिश्माई गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों के लिए एक अबूझ पहेली साबित हुए। उन्होंने अपनी पहली ही उपस्थिति में कुल सात विकेट झटककर भारतीय टीम को मजबूती प्रदान की है।

मानव ने पहली पारी में सिर्फ 33 रन खर्च करते हुए 6 बहुमूल्य विकेट चटकाए, जो उनके शानदार नियंत्रण और विकेट लेने की क्षमता का प्रमाण है। दूसरी पारी में भी उन्होंने एक विकेट अपने नाम किया। यह प्रदर्शन न केवल टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ है, बल्कि भारतीय क्रिकेट के लिए एक नई और होनहार स्पिन प्रतिभा के उभरने का स्पष्ट संकेत भी है। उनके इस दमदार आगाज से टीम प्रबंधन और प्रशंसकों दोनों में उत्साह का माहौल है। इस बेहतरीन प्रदर्शन के साथ ही मानव सुथार ने भारत के लिए टेस्ट डेब्यू पर तीसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ा दर्ज करने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वह इस विशिष्ट सूची में केवल महान स्पिनर नरेंद्र हिरवानी से पीछे हैं, जिन्होंने 1988 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने पहले ही टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 8-8 विकेट लेकर कुल 16 विकेट चटकाए थे। सुथार का यह प्रदर्शन उन्हें भारतीय क्रिकेट इतिहास के पन्नों में दर्ज करा गया है और उन्हें भविष्य के लिए एक उज्ज्वल संभावना के रूप में स्थापित करता है। अपने इस यादगार प्रदर्शन के बाद मानव सुथार ने मैच के दौरान अपनी घबराहट पर काबू पाने और अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को लाचार करने के अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया, जब मैं पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरा, तो मैं काफी सहज महसूस कर रहा था। कुछ गेंदे खेलने के बाद ही मुझे यह समझ आ गया था कि इस विकेट पर स्पिनरों के लिए थोड़ी मदद मौजूद है। उन्होंने आगे कहा, इसके बाद जब मैं गेंदबाजी करने आया और अपना पहला ओवर डाला, तो मुझे वही अहसास हुआ। उसके बाद मेरा पूरा ध्यान केवल सही लाइन, लेंथ और अपनी गति पर नियंत्रण रखने पर था, ताकि मैं लगातार दबाव बना सकूं और विकेट ले सकूं।

जोहान बोथा ने ब्रिस्बेन हीट और क्वींसलैंड के हेड कोच का पद छोड़ा

नई दिल्ली एजेंसी। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान जोहान बोथा ने क्वींसलैंड और ब्रिस्बेन हीट के साथ बतौर कोच अपना कार्यकाल समय से पहले ही समाप्त कर दिया है। उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में एक सीजन बाकी होने के बावजूद दोनों कोचिंग पदों से इस्तीफा दे दिया है। क्वींसलैंड क्रिकेट की तरफ से जारी बयान में कहा गया, 'ब्रिस्बेन हीट और क्वींसलैंड बुल्स के कोच जोहान बोथा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।' क्वींसलैंड क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव टेरी

स्वेनसन ने कहा, 'हमने उस समय में अपने सभी ऑन-फील्ड गोल हासिल नहीं किए हैं, लेकिन जोहान ने क्वींसलैंड और ब्रिस्बेन हीट के खिलाड़ियों की अगली पीढ़ी के विकास में मजबूत योगदान दिया है। हमारे हाई परफॉर्मेंस ग्रुप में जोहान के योगदान को महत्व दिया गया है। हम उन्हें और उनके परिवार को भविष्य में हर सफलता की कामना करते हैं और शेफील्ड शील्ड, वन डे कप और बीबीएल प्रतियोगिताओं में उनके प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं।

महिला टी20 विश्व कप के प्रबल दावेदारों में न्यूजीलैंड सहित ये चार टीमें

ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा है सबसे अधिक बार खिताब

लंदन एजेंसी। 12 जून से इंग्लैंड में शुरु हो रहे महिला विश्वकप क्रिकेट को लेकर सभी टीमें अपनी तैयारियों को अंतिम रुप देने में लगी हैं। इसको लेकर प्रशंसकों में भी जबरदस्त उत्साह है। इस बार खिताब की बड़ी दावेदारों में मौजूद चैम्पियन न्यूजीलैंड सहित कुल चार टीमें ऑस्ट्रेलिया, मेजबान इंग्लैंड और भारत भी है। न्यूजीलैंड टीम का लक्ष्य अपने खिताब को बनाये रखना रहेगा। वहीं भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी इस बार खिताब अपने नाम करने उतरेंगी। पिछले आंकड़ों पर नजर डालें तो महिला टी20 विश्व कप में सबसे अधिक बार ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती है। उसने सबसे अधिक सात बार इस टूर्नामेंट का फाइनल अपने नाम किया है। ऑस्ट्रेलिया केवल एक बार, साल 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ हुए फाइनल में हारी है। इसलिएइस बार भी कंगारुओं को खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है।

वहीं ऑस्ट्रेलिया के बाद, इंग्लैंड की टीम टी20 विश्व कप के फाइनल में सबसे अधिक चार बार फाइनल तक पहुंची है, हालांकि वह केवल एक बार, 2009 में जीत दर्ज करने में सफल रही है। वहीं साल 2012, 2014 और 2018 के फाइनलों में उसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम तीन बार फाइनल में पहुंची है। कीवी टीम ने साल 2009 और साल 2010 में फाइनल खेला है पर उसे दोनों बार इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं साल 2024 में न्यूजीलैंड ने पहली बार इस ट्रॉफी को अपने नाम किया और फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया था। पिछले कुछ समय में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने भी प्रभावित किया है। है। पिछले दो महिला टी20 विश्व कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका ने जगह बनाई है, लेकिन दोनों ही बार वे चैंपियन बनने से रह गई। साल 2023 में उन्हें ऑस्ट्रेलिया ने और

रुतुराज गायकवाड़ का ये रिकार्ड शायद ही कोई तोड़ पाय

मुम्बई एजेंसी। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) की कप्तानी करने वाले बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ के नाम लिस्ट ए क्रिकेट में एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड दर्ज है, जो न केवल असाधारण है बल्कि जिसे तोड़ पाना लगभग असंभव माना जाता है। साल 2022 में विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र की तरफ से खेलते हुए उत्तर प्रदेश के खिलाफ एक ही ओवर में लगातार सात छक्के लगाकर सभी को हैरान कर दिया था। इसी मैच में गायकवाड़ ने 220 रनों की धुआंधार पारी भी खेली थी, जिसने उनके इस ऐतिहासिक कारनामे को और भी यादगार बना दिया। यह अद्भुत घटना उत्तर प्रदेश के गेंदबाज शिवा सिंह के पारी के 49वें ओवर में घटी। गायकवाड़, जो उस समय तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, ने उस

ओवर की पहली छह गेंदों पर लगातार छह छक्के जड़े। इसके बाद, ओवर की अंतिम गेंद नो-बॉल करार दी गई, और गायकवाड़ ने उस फ्री-हिट का भी पूरा फायदा उठाते हुए उसे भी सीमा रेखा के पार भेज दिया। इस प्रकार, एक ही ओवर में उन्होंने सात छक्कों की मदद से कुल 43 रन बटोरे, जो लिस्ट ए क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का नया विश्व कीर्तिमान बन गया। यह एक ऐसा क्षण था जब विपक्षी गेंदबाज शिवा सिंह को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बल्लेबाज एक ही ओवर में इस तरह से गेंद को मैदान के हर कोने में भेज सकता है। क्रिकेट इतिहास में एक ओवर में छह छक्के लगाने का कारनामा कई धुरंधर बल्लेबाजों ने किया है, लेकिन सात छक्के लगाने वाले रुतुराज गायकवाड़ दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं। इस असाधारण उपलब्धि ने क्रिकेट पंडितों और प्रशंसकों को समान रूप से अचंभित कर दिया, और इसे गायकवाड़ की बल्लेबाजी क्षमता का एक बेजोड़ प्रमाण माना गया। उनकी 220 रनों की व्यक्तिगत पारी ने महाराष्ट्र को एक विशाल स्कोर तक पहुंचने में मदद की और मैच में निर्णायक भूमिका निभाई, जिससे यह रिकॉर्ड और भी अधिक चमक उठा।

रुतुराज को सफेद गेंद क्रिकेट का एक तूफानी बल्लेबाज माना जाता है, जिनकी तकनीक और आक्रामक खेल का संयोजन उन्हें बेहद खतरनाक बनाता है। घरेलू स्तर पर उनके लगातार शानदार प्रदर्शन के दम पर ही उन्हें 2021 में टी20 और 2022 में वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने का मौका मिला। भारतीय टीम के लिए वह अब तक 9 वनडे और 23 टी20 मैच खेल चुके हैं। इसके अलावा, गायकवाड़ को एशियन गेम्स में भारतीय टीम की कप्तानी करने का भी गौरव प्राप्त हुआ है।

अंडर-18 हॉकी एशिया में पुरुष और महिला टीम ने लहराया तिरंगा

केंद्रीय खेल मंत्री मांडविया ने सम्मानित किया

नई दिल्ली एजेंसी। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को अंडर-18 एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों को सम्मानित किया। सोमवार को भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मांडविया ने पुरुष टीम को 61.5 लाख रुपए, जबकि महिला टीम को 21 लाख रुपए का चेक सौंपा। काकामिगाहारा में शुक्रवार को खेले गए फाइनल में कप्तान केतन कुशवाहा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने मेजबान जापान को 4-1 से मात देकर खिताब अपने नाम किया। दूसरी तरफ, कप्तान स्वीटी कुजुर के नेतृत्व वाली भारतीय महिला टीम ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में कोरिया पर 3-0 की शानदार जीत दर्ज की। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पुरुष और महिला दोनों टीमों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, 'देश का नाम रोशन करने के लिए दोनों टीमों ने जो कड़ी मेहनत की है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं।

पाक क्रिकेटर खुशदिल शाह का विवादास्पद आरोप

भारत के पक्ष में जाते हैं अधिकांश अंपायरिंग फैसले

लाहौर एजेंसी। शाहिद अफरीदी सहित कई पाकिस्तानी क्रिकेटर हमेशा ही भारत के खिलाफ विवादास्पद बयान देते रहते है। अब इनमें ऑलराउंडर खुशदिल शाह भी शामिल हो गये हैं। जाने खुशदिल ने अब कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले बड़े मुकाबलों में अंपायरिंग को लेकर अधिकतर फैसले भारत के पक्ष में जाते हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंध तनावपूर्ण हैं। ऐसे में खुशदिल के इस प्रकार के आरोप माहौल को और गर्मा सकते हैं। खुशदिल शाह ने सिर्फ अंपायरिंग पर ही सवाल नहीं उठाए, बल्कि उन्होंने मैचों के आयोजन स्थल

के चयन पर भी अपनी आपत्ति जताई है। शाह के अनुसार, अक्सर मैच स्थल भी भारत की पसंद के हिसाब से तय किए जाते हैं, जिससे उन्हें खेल में लाभ मिलता है। पाकिस्तानी क्रिकेटरों की ओर से भारत के खिलाफ इस तरह के आलोचनात्मक बयान नये नहीं हैं और पहले भी कई क्रिकेटर भारत के खिलाफ बयानबाजी करते आये हैं।

एक कार्यक्रम में जब इस क्रिकेटर से भार-पाक मुकाबलों को लेकर पूछा गया तो उसने कहा, मैच में दबाव तो ज्यादा नहीं होता परन्तु इस मैच से भावनाएं बहुत गहराई से जुड़ी होती हैं। दूसरी बात यह है कि मैच में जो चीजें होती हैं, वे अक्सर टीम इंडिया के पक्ष में जाती हैं। जैसे कभी-कभी अंपायर का फैसला उनके पक्ष में चला जाता है, और ड्रेसिंग रूम के कुछ फैसले होते हैं वे भी भारत के पक्ष में होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मैच भी उनकी मर्जी से आयोजित होते हैं।

नेमार इंजरी से रिकवर कर रहे हैंः सीबीएफ

न्यू जर्सी एजेंसी। ब्राजील के स्टार फॉरवर्ड नेमार की इंजरी फीफा विश्व कप 2026 से पहले टीम के लिए सबसे बड़ी चिंता है। हालांकि, ब्राजीलियन फुटबॉल कन्फेडरेशन (सीबीएफ) ने कहा है कि नेमार इंजरी से रिकवरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसका परिणाम भी दिख रहा है। सीबीएफ ने नेमार के बारे में अपडेट देते हुए बताया कि स्टार फॉरवर्ड के दाहिने पैर में ग्रेड टू पिंडली की चोट से उनकी रिकवरी का पता लगाने के लिए एमआरआई स्कैन किया गया। 34 साल के नेमार की रिकवरी उम्मीद के मुताबिक है। वह एक खास योजना के तहत इलाज लेते रहेंगे। शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, 'सीबीएफ ने यह नहीं बताया कि वह खेलने के लिए कब तक उपलब्ध होंगे। ' स्थानीय मीडिया के मुताबिक वह कम से कम दूसरे ग्रुप मैच तक उपलब्ध नहीं रहेंगे।

नेमार, ब्राजील के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 128 इंटरनेशनल मैचों में 79 गोल किए हैं। इंजरी की वजह से अक्टूबर 2023 के बाद से वह राष्ट्रीय

टीम के लिए नहीं खेले हैं। हाल में उन्हें अपने क्लब सैंटोस के लिए खेलते हुए मई इंजरी हुई थी। स्टार खिलाड़ी की पिंडली में चोट लगी थी।

ब्राजील अपने वर्ल्ड कप कैंपेन की शुरुआत शनिवार को मोरक्को के खिलाफ करेगा। इसके बाद उसका सामना हैती और स्कॉटलैंड से होगा। नेमार शुरुआती दो मैचों से बाहर रह सकते हैं। ब्राजील अगले साल रिकॉर्ड 23वीं बार फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा। ब्राजील एकमात्र ऐसी टीम है जिसने विश्व कप के हर एडिशन में हिस्सा लिया है।

एजेण्डा बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन न देने पर होगी कार्रवाई

तय मात्रा से अधिक खाद लेने वाले किसानों का सत्यापन कर रिपोर्ट दें : कमिश्नर

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। कमिश्नर बीएस जामोद ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि संभागीय समीक्षा बैठक और कमिश्नर कान्फ्रेंस के एजेण्डा बिन्दुओं में 10 जून तक पालन प्रतिवेदन दें विभागीय बिन्दुओं में की गई कार्यवाही ऑनलाइन दर्ज कराएं इस संबंध में सभी अधिकारियों को कई बार सचेत किया जा चुका है समय सीमा का पालन न होने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। समीक्षा बैठक कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित की गई। बैठक में कमिश्नर ने कहा कि सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन में सौ दिन से अधिक लंबित प्रकरणों का निराकरण कराएं। इसमें लेबल-1 पर अनअटेंडेड रहने वाले सभी आवेदनों में संबंधित अधिकारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करें सीएम हेल्पलाइन में मई माह में दर्ज आवेदनों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण कराकर विभाग की रैंकिंग में सुधार कराएं बैठक में कमिश्नर ने कहा कि संयुक्त संचालक कृषि तय मात्रा से अधिक खाद लेने वाले किसानों का सत्यापन करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करें प्रत्येक किसान से संपर्क करके अधिक खाद खरीदने का कारण ज्ञात करें इन किसानों को फसलों में खाद के संतुलित उपयोग और प्राकृतिक खेती की समझाइश दें संभाग के सतना, मैहर और रीवा जिलों में नरवाई जलाने की घटना बड़ी संख्या में हुई हैं किसानों को नरवाई के उचित प्रबंधन के लिए जागरूक करें किसान संगोष्ठी तथा अन्य माध्यमों से किसानों को नरवाई से खाद बनाने के लिए प्रेरित करें अभी खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है जिला विकासखण्ड तथा ग्राम स्तर के कृषि विभाग के अधिकारी अभियान के दौरान लगातार क्षेत्र का भ्रमण करके किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक तथा प्राकृतिक खेती के लिए जागरूक करें संयुक्त संचालक पशुपालन दुधारू पशुओं के नस्ल सुधार के प्रयासों की मानीटरिंग करें। संभाग के सभी जिलों में कृत्रिम गर्भाधान की प्रगति बहुत कम है पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य भी 30 जून तक शत-प्रतिशत पूरा कराएं इसकी हर सप्ताह रिपोर्ट प्रस्तुत करें बैठक में कमिश्नर ने कहा कि आगामी वर्षाकाल में अतिवृष्टि और बाढ़ से राहत और बचाव के लिए समुचित प्रबंध करें। आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी अधिकारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें। सड़क सुरक्षा समिति की हर माह बैठक आयोजित कर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के प्रयासों की समीक्षा करें। राहवीर योजना तथा प्रधानमंत्री राहत योजना का समुचित प्रचार-प्रसार कराएं। सरसी आईलैण्ड तथा संभाग के अन्य जलाशयों में नाव एवं मोटरबोट में सुरक्षा के प्रबंध कराएं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी तथा बाणसागर बांध में भी नौकायन में सुरक्षा के प्रबंधों की समीक्षा करें कई जिलों से हैण्डपंपों के अवैध कब्जे की सूचनाएं मिली हैं अधीक्षण यंत्री पीएचई हैण्डपंपों से अवैध कब्जा हटाने के लिए अभियान चलाएं। सभी जिलों में 12 से 18 जून तक जनकल्याण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। संभागीय अधिकारी इन शिविरों में उपस्थित रहकर आमजनता के आवेदनों के निराकरण तथा महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रचार प्रसार की निगरानी करें बैठक में कमिश्नर ने जल गंगा संवर्धन अभियान पेयजल व्यवस्था वर्षाजनित रोगों से बचाव खाद और बीज के वितरण तथा स्कूलों में विद्यार्थियों के प्रवेश के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि ई आफिस से ही समस्त फाइलों का मूवमेंट करें। जिला और विकासखण्ड स्तर पर ई आफिस व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू कराएं। बैठक में संयुक्त आयुक्त सुदेश मालवीय, संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी, एसडीओ वन हितेश खण्डेलवाल तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

बेलगवा पंचायत में पीसीसी सड़क निर्माण पर उठे सवाल, जांच न होने से ग्रामीणों में नाराजगी

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। जनपद पंचायत जवा अंतर्गत ग्राम पंचायत बेलगवा में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और कथित अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पंचायत में निर्माण कार्यों में मानकों की अनदेखी कर राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है जानकारी के अनुसार, बेलगवा गांव मोड़ से इटावा गांव की ओर जाने वाली सड़क पर पीसीसी निर्माण कार्य में बड़े बोल्डरों के ऊपर निम्न गुणवत्ता की सामग्री डालकर सड़क बनाई गई। ग्रामीणों का कहना है कि कार्य में मानक बालू, गिट्टी और सीमित मात्रा में सीमेंट का उपयोग किया गया, जिससे सड़क की गुणवत्ता प्रभावित हुई है स्थानीय लोगों के अनुसार, कार्य के दौरान ही संबंधित अधिकारियों को शिकायत दी गई थी, लेकिन जांच या कार्यवाही के बजाय निर्माण कार्य जारी रहा और भुगतान भी कर दिया गया। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि कार्य को कागजों में सही दर्शाने के लिए सड़क किनारे ऊंचाई दिखाकर निर्माण पूरा बताया गया, जबकि वास्तविकता में सड़क की गुणवत्ता बेहद खराब है लगभग आठ माह पूर्व निर्मित यह सड़क अब जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि निर्माण कार्यों में जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है और जांच न होने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने पूरे निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा कथित अनियमितताओं की राशि की वसूली करने की मांग की है ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वहीं, प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

शिक्षकों एवं पेंशनरों को चतुर्थ क्रमोन्नति समयमान वेतनमान का लाभ नहीं, अधिकारियों के रवैये पर सवाल : आबाद खान

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। मध्य प्रदेश शासन एवं वित्त विभाग द्वारा अप्रैल 2026 में जारी आदेशों के बावजूद रीवा जिले में शिक्षकों और पेंशनरों को चतुर्थ क्रमोन्नति समयमान वेतनमान का लाभ अब तक नहीं मिल सका है जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में पात्र कर्मचारियों और पेंशनरों की सूची जारी कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के पूर्व उप प्रांत अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स एसोसिएशन रीवा संभाग के प्रवक्ता आबाद खान ने बताया कि अगस्त 2023 में शासन ने यह आदेश दिया था कि सीधी भर्ती से नियुक्त शासकीय सेवकों को उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से 35 वर्ष सेवा पूर्ण होने पर या 1 जुलाई 2023 के बाद 35 वर्ष सेवा पूरी करने पर यह लाभ मिलेगा। प्रथम से लेकर चौथी श्रेणी तक सभी पात्र कर्मचारियों के लिए यह सुविधा स्वीकृत की गई थी आबाद खान ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार पात्र कर्मचारियों ने आवश्यक दस्तावेज और गोपनीय चरित्रावली जिला कार्यालयों में जमा कर दी थी। अधिकांश विभागों में लाभ मिल चुका है लेकिन शिक्षा विभाग में प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से प्रक्रिया लंबित है अप्रैल 2026 में शासन और वित्त विभाग ने पुनः आदेश जारी कर शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और पेंशनरों को भी लाभ सुनिश्चित किया उन्होंने आरोप लगाया कि तीन माह से अधिक समय बीतने के बावजूद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रीवा में सूची जारी नहीं की गई है परिणामस्वरूप हजारों शिक्षक और पेंशनर शासन द्वारा स्वीकृत लाभ से वंचित हैं आबाद खान ने जिला शिक्षा अधिकारी संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, संभागायुक्त और कलेक्टर रीवा से तत्काल सूची एवं आदेश जारी करने की मांग की उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्यवाही नहीं हुई तो शिक्षक और पेंशनर संगठन संयुक्त रूप से धरना और प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों की होगी।

फर्जी भूमि विक्रय के मामले में बिचौलियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू में दर्ज हुआ आपराधिक प्रकरण

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। ग्राम सलैया में फर्जी भूमि स्वामी बनकर जमीन विक्रय करने के मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने कार्रवाई करते हुए बिचौलियों और फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करने वाले आरोपियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। इस मामले में वास्तविक भूमि स्वामी को जमीन के बदले कोई धन राशि प्राप्त नहीं हुई प्राप्त शिकायत के अनुसार आरसीसीपीएल प्राइवेट लिमिटेड सीमेंट कंपनी को लगभग 28.00 लाख रुपये में 0.700 हेक्टेयर भूमि बिचौलियों के माध्यम से फर्जी विक्रेता द्वारा विक्रय कराई गई। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि मैहर जिले के ग्राम सलैया में प्रतीक राय निवासी नागपुर, महाराष्ट्र की भूमि को उसके स्वामित्व में रहते हुए

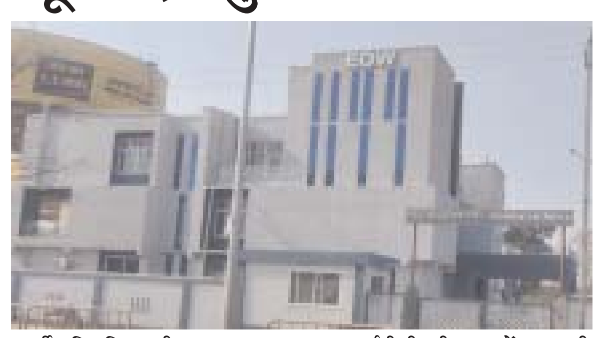

फर्जी/प्रतिरूपित प्रतीक राय नामक व्यक्ति ने फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड के माध्यम से राजकुमार गौतम के नाम विक्रय कर दिया इसके बाद उक्त भूमि आरसीसीपीएल प्राइवेट लिमिटेड, भरौली सीमेंट फैक्ट्री को राकेश बाफना को 28.00 लाख रुपये में विक्रय कर दी गई, जबकि वास्तविक स्वामी प्रतीक राय को कोई धन राशि नहीं मिली आरोपियों पर आईपीसी की धाराओं 120-बी (साजिश), 420 (धोखाधड़ी), 467, 468, 471 (फर्जीवाड़ा और दस्तावेजों के प्रयोग) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। ईओडब्ल्यू द्वारा मामले की गहन जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है इस कार्रवाई से जिले में फर्जी भूमि विक्रय और बिचौलियों द्वारा आम लोगों को ठगने के खिलाफ कड़ा संदेश गया है, साथ ही वास्तविक भूमि स्वामियों के हितों की सुरक्षा की दिशा में प्रशासन ने कदम बढ़ाया है।

अपराधिक प्रकरण में शामिल आरोपीगण हैं:

1. राजकुमार गौतम, ग्राम मनटोलवा, मैहर
2. संजय मिश्रा, ग्राम सलैया, मैहर
3. धनेन्द्र सिंह, हरनामपुर, मैहर
4. आलोक गौतम, प्रेम विहार कालोनी, रघुराजनगर, सतना
5. अमित चतुर्वेदी, ग्राम सोहावल, रघुराजनगर, सतना
6. फर्जी/प्रतिरूपित प्रतीक राय, चौपड़ा कालोनी, मैहर
7. अन्य संबंधित व्यक्ति

रीवा संभाग ई आफिस में लगातार प्रदेश में प्रथम स्थान पर

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। प्रशासनिक नवाचार के तहत ई आफिस व्यवस्था लागू की गई है अब कार्यालयों के अंदर तथा अन्य कार्यालयों में फाइलों का संचालन ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है ई आफिस व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करके रीवा संभाग में संभागीय रैंकिंग में अक्टूबर माह से लगातार प्रदेश में प्रथम स्थान पर बना हुआ है इस संबंध में कमिश्नर बीएस जामोद ने बताया कि रीवा संभाग में कुल 22384 फाइलें ई आफिस में क्रिएट की गईं तथा 85117 फाइलों का मूवमेंट हुआ प्रदेश में दूसरे स्थान पर नर्मदापुरम संभाग है जिसमें 6540 फाइलों का क्रिएशन तथा 53486 फाइलों का मूवमेंट हुआ है।

कमिश्नर और अधिकारी ई-रिक्शा से पहुंचे कार्यालय, पेट्रोलियम बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। रीवा में पेट्रोलियम पदार्थों की बचत और पर्यावरण संरक्षण को लेकर अगस्त 2025 से लगातार अभियान चलाया जा रहा है इसी पहल को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से कमिश्नर बीएस जामोद की विशेष पहल पर मंगलवार को संभागीय अधिकारी कर्मचारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी ई-रिक्शा, साइकिल अथवा इलेक्ट्रॉनिक वाहन का उपयोग करके कमिश्नर कार्यालय पहुंचे कमिश्नर कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में सभी अधिकारी इस संदेश के माध्यम से आमजन को प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं

कि पेट्रोलियम पर निर्भर वाहनों के स्थान पर हर सप्ताह कम से कम एक दिन साइकिल या इलेक्ट्रॉनिक वाहन का उपयोग किया जाए। बीएस जामोद ने कहा कि यह केवल एक प्रतीकात्मक कदम नहीं है, बल्कि छोटे-छोटे प्रयासों के माध्यम से पेट्रोलियम बचत और स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे अपने व्यवहार से जनता में जागरूकता फैलाएं। इस दौरान उपस्थित अधिकारी और कर्मचारी भी ई-रिक्शा का उपयोग कर कार्यालय पहुंचे जिससे यह संदेश स्पष्ट हुआ कि सरकारी अधिकारी स्वयं अपने प्रयासों से पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत का उदाहरण पेश कर सकते हैं रीवा में पिछले 42 सप्ताहों से यह अभियान चलाया जा रहा है और जनता में भी इसकी सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कमिश्नर ने बताया कि इस प्रकार के कदम न केवल पेट्रोलियम की बचत में सहायक हैं, बल्कि वायु प्रदूषण को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे प्रयासों का सामूहिक प्रभाव लंबे समय में बड़े बदलाव ला सकता है अधिकारियों ने बैठक में अपने विभागों में पेट्रोलियम बचत, ई-वाहन उपयोग और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यक्रमों की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

10 मामलों में 241 पाव शराब जब्त :नईगढ़ी पुलिस ने अवैध शराब कारोबार पर की कार्रवाई

मीडिया ऑडीटर, मऊगंज (निप्र)। नईगढ़ी पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है मंगलवार को पुलिस ने विभिन्न गांवों में दबिश देकर 10 मामलों में कुल 241 पाव देशी प्लेन शराब जब्त की जब्त शराब की अनुमानित कीमत 24,100 रुपए बताई गई है यह कार्रवाई मऊगंज पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार जैन के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह परिहार और एसडीओपी सचि पाठक के मार्गदर्शन में की गई थाना प्रभारी उप निरीक्षक ऋषि कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर मंगलवार को अलग-अलग स्थानों में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की पुलिस टीम ने टीम ने बंधवा मोड़, डिलहा, बेलहा, देवगना, जोरौट, सेनुआ, सोनवर्षा, कुशहा और पिपरा सहित कई गांवों

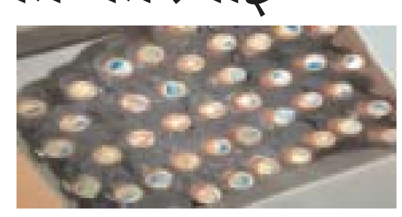

में दबिश दी इस दौरान विभिन्न आरोपियों के कब्जे से अवैध रूप से बिक्री के लिए रखी गई देशी शराब बरामद की गई पुलिस ने विपिन पटेल, संजय रावत, राजेश साकेत, विक्रम सिंह, राहुल सिंह, ममता प्रजापति, संतोष जायसवाल, राजलाल यादव, रमेश पटेल और दिनेश पटेल के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(ए) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। सभी आरोपियों को न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं नईगढ़ी पुलिस की इस कार्रवाई को अवैध शराब कारोबार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर लगातार अभियान जारी रहेगा और ऐसे कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी इस कार्रवाई में थाना प्रभारी ऋषि कुमार द्विवेदी के साथ उप निरीक्षक आरपी वर्मा, उप निरीक्षक अनंत विजय सिंह, सहायक उप निरीक्षक पवन अवस्थी, नारायण प्रसाद पांडे, नरेंद्र मिश्रा सहित अन्य पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

प्रभारी कलेक्टर सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने की जनसुनवाई जिला स्तर पर आयोजित जनसुनवाई में 453 आवेदकों के प्राप्त हुए आवेदन

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई में आज कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में प्रभारी कलेक्टर अक्षत जैन सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने लोगों की समस्यायें सुनीं जिला स्तरीय जनसुनवाई में प्राप्त 453 आवेदनों को संबंधित विभागीय अधिकारियों को समुचित कार्यवाही के लिये प्रेषित कर आवश्यक निर्देश दिये गये जिला पंचायत के सीईओ मेहताब सिंह गुर्जर, अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी, डिप्टी कलेक्टर राजेश कुमार सिन्हा, सुधीर कुमार बेक, एसडीएम हुजूर डॉ. अनुराग तिवारी ने भी आवेदकों की समस्यायें सुनीं जनसुनवाई में गोरगांव के निवासियों ने उपयुक्त स्थल पर पंचायत भवन निर्माण

कराने का आवेदन दिया प्रभारी कलेक्टर ने परीक्षण कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये। ग्राम बघरा के रहवासियों ने अपने आवेदन में नाला न होने से वर्षा का पानी घरों में घुसने की समस्या बताई प्रभारी कलेक्टर ने सीईओ जनपद को कार्यवाही करने के निर्देश दिये अजगरहा निवासी राजकली सिंह के सीमांकन/नक्शा तरमीम करने, रामनरेश गुप्ता के खसरा सुधार कराने सगरा निवासी राजरतन पाठक के अतिक्रमण हटाने सिरमौर निवासी ममता साकेत के भूमिहीन को भूमि प्रदाय करने के आवेदनों पर संबंधित तहसीलदारों को समुचित कार्यवाही करने के निर्देश जनसुनवाई में दिये गये इसी प्रकार सोनवर्षा के आकाश पटेल के बिना अनुमति खनन को रोकने के आवेदन पर खनिज अधिकारी को जगन्नाथ प्रजापति के भू अर्जन राशि प्रदाय करने के आवेदन पर एसडीएम मनगवां को, पार्वती प्रजापति के छात्रवृत्ति प्रदाय करने के आवेदन पर जिला संयोजक को तथा अकौरी

के शिवकुमार विश्वकर्मा में आवास पट्टा दिलाने के आवेदन पर सीईओ जनपद जवा को कार्यवाही करने के निर्देश प्रभारी कलेक्टर ने दिये जनसुनवाई में कुठुलिया के रामकुमार कोरी ने कच्चा मकान क्षतिग्रस्त होने पर मुआवजा देने के आवेदन पर तहसीलदार जवा को तथा इटौरा निवासी सवित्री के हैण्डपंप सुधार कराने के आवेदन पर पीएचई विभाग को कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। इस अवसर पर जिला स्तरीय अधिकारी कलेक्टर कार्यालय के सभागार में उपस्थित रहे तथा खण्ड स्तरीय अधिकारी वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जुड़े।

रीवा में बढ़ी गर्मी की तपिश, 40 डिग्री पहुंचा पारा, 12 जून से राहत के आसार

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। शहर में जून की गर्मी लगातार अपना असर दिखा रही है। मंगलवार को रीवा का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया सुबह से ही तेज धूप निकलने के कारण दोपहर के समय गर्मी और लू जैसे हालात बने रहे दिनभर चलने वाली गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी जिससे सड़कों और बाजारों में भीड़ अपेक्षाकृत कम दिखाई दी मौसम विभाग के अनुसार पिछले तीन दिनों से तापमान लगातार ऊंचे स्तर पर बना हुआ है 6 जून को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था इसके बाद 7 जून को तापमान बढ़कर 39 डिग्री पहुंच गया जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। 8 जून को भी अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लगातार बढ़ते तापमान के कारण लोगों को गर्मी के साथ उमस का भी सामना करना पड़ रहा है भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले दो से तीन दिनों तक मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है 10 जून को अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं 11 जून को अधिकतम तापमान 39 डिग्री और 12 जून को 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है इस दौरान आंशिक बादल छाने और कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है जिससे तापमान में मामूली गिरावट आने के संकेत हैं शहरवासियों का कहना है कि दोपहर के समय घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है लोग अब मानसून की पहली बारिश का इंतजार कर रहे हैं।

स्वत्वाधिकारी मुद्रक/प्रकाशक संदीप द्विवेदी द्वारा मीडिया ऑडीटर पब्लिकेशन प्रा.लिमि. राजीव मार्ग निराला नगर रीवा से मुद्रित कर मीडिया ऑडीटर कार्यालय राजीव मार्ग निराला नगर रीवा से प्रकाशित, **संपादक संदीप द्विवेदी**, आर.एन.आई नं. 69082/97, डाक पंजीयन क्र.- म. प्र./ रीवा संभाग/ 46/2023-2025, प्रधान कार्यालय रीवा (सिटी कार्यालय चक्रधर सिटी सेंटर रीवा) फोन. नं. 9589645803, 7974467831 Mediaauditor1@gmail.com सभी विवादों का न्याय क्षेत्र रीवा होगा।